राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 वर्ष-8,अंक-237 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पीएम आज 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में औद्योगिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली

पीएम मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। जहां वह नंदयाल जिले के श्रीशैलम में भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा और दर्शन करेंगे।

इसके बाद दोपहर को पीएम मोदी श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कुरनूल जाएंगे, जहां वे करीब 2:30 बजे करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा और दर्शन करेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की अनूठी विशेषता एक ही मंदिर परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ का सह-अस्तित्व है, जो इसे पूरे देश में अनूठा बनाता है। पीएम मोदी शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा करेंगे, जो एक स्मारक है जिसमें एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर चार प्रतिष्ठित किलों–प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी–के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। श्रीशैलम में छत्रपति शिवाजी महाराज की 1677 में इस पवित्र तीर्थस्थल की ऐतिहासिक यात्रा के उपलक्ष्य में की गई थी। पीएम मोदी कुरनूल में करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समेत प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो क्षेत्रीय अवसंरचना को बढ़ाने, औद्योगीकरण में तेजी लाने और राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।

इसके अलावा पीएम मोदी 2,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में 765 केवी डबल-सर्किट कुरनूल-3 पूलिंग स्टेशन-चिलकलुरिपेटा पारेषण लाइन का निर्माण शामिल है, जिससे रूपांतरण क्षमता में 6,000 एमवीए की बढ़ोतरी होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर पारेषण संभव होगा और देश के विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी कुरनूल में ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा।

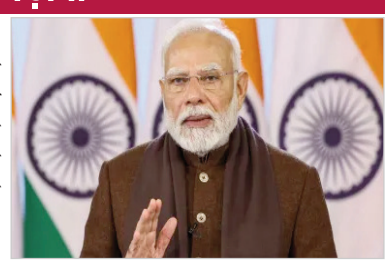

भारत और सऊदी अरब रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली भारत और सऊदी अरब ने रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जाहिर। यह सहमति एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान बनी, जो रियाद में आयोजित हुई। भारत की ओर से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग और सऊदी अरब की ओर से उद्योग एवं खनिज मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने की। वहीं सऊदी अरब की ओर से उपमंत्री इंजीनियर खलील बिन इब्राहिम बिन सलमाह बैठक में मौजूद रहे। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापारः 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर। रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत (करीब 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर) का योगदान है। इस बैठक में दोनों देश के अधिकारियों ने निवेश बढ़ाना और नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति जाहिर की। सऊदी अरब की विशेषज्ञता पेट्रोकेमिकल्स में और भारत की मजबूती विशेष रसायनों में है। भारत के पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्रों में सऊदी निवेश की संभावनाएँ। दोनों देशों की प्रमुख कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाना। अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास में सहयोग। इस टिकाऊ और पारस्परिक लाभकारी संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत की पटाखा राजधानी शिवकाशी..... बदलाव को अपनाकर अब ग्रीन पटाखों को तैयार कर रही

शिवकाशी दीपावली का त्यौहार आते ही पूरे देश में पटाखों की मांग बढ़ जाती है, और मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु का छोटा-सा शहर शिवकाशी चर्चा का केंद्र बन जाता है। इससे न केवल भारत की पटाखा राजधानी कहते है, बल्कि इसकी औद्योगिक सक्रियता के कारण यह 'मिनी जापान' के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहां देश के करीब 90 प्रतिशत पटाखे तैयार होते हैं और अब यह शहर धीरे-धीरे ग्रीन पटाखों (पर्यावरण-अनुकूल पटाखों) के उत्पादन की दिशा में कदम बड़ा रहा है। शिवकाशी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 1,100 से अधिक बड़े कारखाने और 8,000 से ज्यादा छोटे उद्योगिक इकाइयाँ पटाखे बनाने का काम करती हैं। यह शहर न केवल पटाखों बल्कि माचिस और छपाई उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। हजारों परिवारों की आजीविका पटाखा कारोबार से जुड़ी हुई है। शिवकाशी को मिनी जापान इसलिए कहते है, क्योंकि यहां की उद्योगिक दक्षता, तकनीकी निपुणता और कड़ी कार्यसंस्कृति जापान जैसी मानी जाती है। दशकों से यहां के लोग पारंपरिक तरीकों से पटाखों और माचिस के निर्माण में माहिर हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में प्रदूषण के कारण ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ी है। यह देखकर शिवकाशी में भी इन पर्यावरण-अनुकूल पटाखों का निर्माण शुरू हो चुका है। हालांकि, फिलहाल इनका उत्पादन पारंपरिक पटाखों की तुलना में काफी कम है। ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम पेरियोडेट जैसे महंगे रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। कुछ तत्व जैसे स्ट्रोंटियम नाइट्रेट नमी सोख लेते हैं, जिससे बरसात के मौसम में उत्पादन बाधित हो जाता है। इन पटाखों की शेल्फ लाइफ भी कम होती है, जिससे इनके भंडारण और बिक्री पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारंपरिक पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद शिवकाशी के पटाखा उद्योग को लगभग 15 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

बिहार के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी सूची, मैथिली ठाकुर और आईपीएस अधिकारी मिश्रा को टिकट

नई दिल्ली बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी दूसरी सूची जारी की है। पार्टी ने सूची में 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर और आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का है। एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुईं मैथिली को बीजेपी ने अलीनगर विधानसभा सीट से उतारा है। इसके साथ, बीजेपी ने हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं, मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार पर भरोसा जताया गया है। गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदार नाथ सिंह को मैदान में उतरा गया है। छपरा सीट से छोटी कुमारी को बीजेपी ने टिकट दिया है। सोनपुर सीट से विनय कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट बने है। रोसड़ा (अ.जा) सीट से बीरेंद्र कुमार को टिकट मिला है। बाढ़ विधानसभा सीट से सियाराम सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अगिआंव सीट से महेश पासवान को टिकट मिला है। शाहपुर सीट से राकेश ओझा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट मिला है।

चीन ब्रह्मपुत्र बना रहा सबसे बड़ा बांध, पड़ोसी देशों पर बनाना चाहता है दबाव

भारत ने जलविद्युत योजना का अनावरण का फैसला कर दिया जवाब

नई दिल्ली

चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर मनमानी करने की सोच रहा है। इस बांध के जरिए वह अपने पड़ोसी देशों को रौंदकर अपना व्यापार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब भारत ने भी इसका जवाब देने का फैसला लिया है। दरअसल, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ही 6.4 लाख करोड़ रुपए की जलविद्युत योजना का अनावरण किया। भारत के इस फैसले के पीछे रणनीति है जो कि भविष्य में भारत के कई राज्यों को फायदा पहुंचाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जलविद्युत परियोजना के बनने से पूर्वोत्तर राज्यों की बिजली की जरूरत आसानी से पूरी होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए 2047 तक ब्रह्मपुत्र बेसिन से 76 गीगावाट से ज्यादा जलविद्युत क्षमता स्थानांतरित करने के लिए 6.4 ट्रिलियन रुपए की पारेषण योजना तैयार की है। सोमवार को जारी रिपोर्ट में सीईए ने कहा कि इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के 12 उप-बेसिनों में 208 बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनकी संभावित क्षमता 64.9 गीगावाट और पंप-स्टोरेज संयंत्रों से अतिरिक्त 11.1 गीगावाट है। बेसिन की सीमापारीय प्रकृति और चीन से निकटता के कारण जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की योजना एक रणनीतिक मुद्दा बन गया है। चीन के ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाए जाने के बाद भारत को डर सता रहा है कि यह बांध भारतीय क्षेत्र में पानी के प्रवाह को 85 फीसदी कम कर सकता है। इतना ही नहीं, कभी युद्ध की स्थिति आई तो चीन इस बांध का दुरुपयोग भी कर सकता है। इससे ब्रह्मपुत्र के निचले इलाके को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

बता दें ब्रह्मपुत्र नदी, जो चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत-बांग्लादेश से होकर बहती है, अपने भारतीय क्षेत्र में विशेषकर चीन सीमा के निकट अरुणाचल प्रदेश में, अहम जलविद्युत क्षमता रखती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है और भारत की अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता का 80 फीसदी से ज्यादा इसमें समाहित है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में 52.2 गीगावाट की क्षमता है। बता दें चीन ने जुलाई में दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में भारत की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र पर एक बड़े बांध का निर्माण शुरू किया है। भारत ने इस साल की शुरुआत में इस परियोजना को लेकर चिंता जताई थी।

सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर को

नई दिल्ली

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

बात दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत मांगी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ को सुनवाई करनी है। इससे पहले, केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों से जवाब मांगा गया था।

लेह प्रशासन ने अपने हलफनामे में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक की हिरासत का बचाव किया है।

लेह के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि हिरासत आदेश 26 सितंबर को पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट थे और अभी भी संतुष्ट हैं कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए। हिरासत का आधार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों को बताया गया है। प्रशासन ने अवैध हिरासत और अनुचित व्यवहार के आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि हिरासत संविधान के अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए की गई थी।

राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए खोला पैसा का पिटारा

नई दिल्ली

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बुधवार को इस बारे में जानकारी देकर रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू होती हैं। वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी के तहत अनुदान 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी किया गया है।

यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन मिलेगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं। वहीं शैक्षणिक अनुदान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी किया गया है। यह सहायता अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कक्षा 1 से स्नातक तक या दो वर्षीय परास्नातक कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं को दी जाएगी। विवाह अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। विवाह अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी किया गया है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अनुदान अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी की गई नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी। इससे प्रति वर्ष करीब 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा।

केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर दिल्ली एचसी ने ईडी पर दिखाई सख्ती

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर श्वष्ठ को आखिरी मौका दिया है। अगर ईडी दलीलें पेश नहीं कर पाती, तो कोर्ट अंतिम फैसला सुना सकता है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को है। केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए ईडी को आखिरी मौका दिया। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई में देरी नहीं होगी। कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसावी। राजू की ओर से स्थगन की मांग की, क्योंकि उस समय राजू सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पहले ही बिना किसी कारण के 9 स्थगन ले चुका है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून 2024 तक वैध थी। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने 25 जून 2024 को इसे स्थगित कर दिया।

वहीं, जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाई। इस मामले में अगली सनवाई 10 नवंबर को है। अगर ईडी अपनी दलीलें नहीं रख पाती, तो कोर्ट याचिका पर अंतिम फैसला ले सकता है।

3 राज्यों में सीबीआई ने की छापेमारी, अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 3 गिरफ्तार

निर्दोष लोगों को कंपनियों में पार्ट-टाइम रोजगार का झांसा देकर निदेशक बनाया था

नई दिल्ली

सीबीआई ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड मामले में सोमवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक साथ कई ठिकानों पर छापे मारे थे। यह कार्रवाई सीबीआई के ऑपरेशन चक्र-5 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करना है। इस दौरान एजेंसी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यह मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर समन्वय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि देशभर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था। आरोप है कि यह गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब के झूठे वादों से फंसाकर उनसे भारी रकम वसूलता था। जांच से पता चला है कि इस नेटवर्क में भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक शामिल थे। आरोपियों ने देशभर में, खासतौर पर बेंगलुरु में फर्जी कंपनियों का जाल बिछाया था। इन कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन को इधर-उधर किया था। कई निर्दोष लोगों को ई-कॉमर्स या फिनटेक कंपनियों में पार्ट-टाइम रोजगार का झांसा देकर कंपनी का निदेशक बनाया था, ताकि फर्जी बैंक खातों और डिजिटल हस्ताक्षरों के जरिए धन का प्रवाह तय किया जा सके। सीबीआई के मुताबिक अपराधियों ने एक संगठित और उन्नत साइबर ठगी का तरीका अपनाया था। इसमें डिजिटल विज्ञापन, बल्क एसएमएस कैंपेन, और सिम बॉक्स तकनीक के जरिए फर्जी निवेश योजनाओं को प्रमोट किया जाता था। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भर्ती किए लोगों से केवाईसी दस्तावेज लेकर फर्जी प्रोफाइल और कंपनियां बनाई गईं। इन फर्जी कंपनियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले गए, जिनमें पीड़ितों से ठगे गए पैसे जमा कराए जाते थे। जांच में यह भी पता चला है कि ठगों ने मिले धन को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया और पेमेंट गेटवे, यूपीआई प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के जरिए धन की हेराफेरी की गई। ठगी के पैसों का बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी, सोने में बदला गया या गुप्त चैनलों के जरिए विदेश भेजा गया। सीबीआई ने यह भी पाया कि कई भारतीय नागरिक विदेशी संस्थाओं के निर्देशन में काम कर रहे थे, जो अवैध ऑनलाइन जुए और निवेश ठगी ऑपरेशंस में शामिल थीं।

एजेंसी ने कहा कि अब तक कई संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की पहचान की हो चुकी है, जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं। यह मामला भारत और विदेशों में फैले वृहद साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा है। सीबीआई ने कहा इस मामले में अन्य भारतीय और विदेशी आरोपियों की तलाश है, ठगी की रकम का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन चक्र-5 के तहत एजेंसी का लक्ष्य ऐसे ट्रांसनेशनल साइबर फॉड नेटवर्क्स को खत्म करना है, जो कई देशों में फैले हैं और भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इस्राइल- हमास युद्धविरामः आशा की किरण या अस्थायी विराम ?

(लेखक-- ललित गर्ग)

गाज़ा की धरती लम्बे दौर से संघर्ष, हिंसा, विनाश और तबाही की त्रासदी की गवाह रही है, आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ शांति की एक हल्की किरण दिखाई तो देती है, परंतु उसके चारों ओर धुएँ और राख का अंधकार अब भी विद्यमान है। हाल ही में हुए युद्ध-विराम ने न केवल मध्यपूर्व बल्कि समूचे विश्व को राहत की एक साँस दी है। गाजा में अमन-चैन की ओर जो सुखद कदम बढ़े हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। परंतु यह सवाल भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या यह शांति स्थायी होगी, या यह केवल अगली लड़ाई से पहले का ठहराव भर है? समूची दुनिया चाहती है कि यह युद्ध विराम स्थायी हो क्योंकि इस्राइल और हमास के संघर्ष ने करीब बाइस लाख से अधिक लोगों को बेघर करके भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिये समझौते के पहले चरण को पूरी तरह से लागू करना बेहद जरूरी होगा। जिसमें बंधकों व कैदियों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता को अनवरत जारी रखना और इस्राइली सेनाओं की गाजा के मुख्य शहरों से आंशिक वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। यह सब दूसरे चरण की बातचीत पर निर्भर हैं।

यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसके बाद ही दूसरे चरण की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह बेहद मुश्किल चुनौतियों वाला चरण होगा। इस दौरान कई संवेदनशील मुद्दे सामने होंगे। सबकी निगाह इस पर होगी कि शांति समझौते के अगले चरण कब पूरे होते हैं और वे सही तरह पूरे होते भी हैं या नहीं? इस पर संशय इसलिए है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कि इजरायली सेना गाजा में कितना पीछे हटेगी और वहां के प्रशासन को संचालित करने का कैसा तंत्र तैयार होगा और क्या उस पर हमास सहमत होगा? इसके अतिरिक्त जहां हमास को हथियार छोड़ने हैं, वहीं इजरायल को स्वतंत्र फिलस्तीन देश की राह आसान करनी है। हमास का कहना है कि हथियार तब छोड़े जाएंगे, जब स्वतंत्र फिलस्तीन का रास्ता साफ होगा। इस पर इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है। यह ठीक है कि स्वयं की ओर से प्रस्तावित गाजा शांति समझौते पर अमल शुरू होने के अवसर पर मिस्र जाने के पहले इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पहल को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना का पथ करार दिया और इजरायली प्रधानमंत्री से ईरान से समझौता करने को कहा। ऐसे किसी समझौते की सूरत तब बनेगी, जब ईरान इजरायल को मिटाने की अपनी जिद छोड़ेगा।

बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस्राइल-हमास जोखिमभरा युद्धविराम समझौता नाजुक बना हुआ है। इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। इस संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि प्रमुख हितधारकों की ओर से गंभीर एवं ईमानदार प्रयास लगातार होते रहें।

गाज़ा की वर्तमान स्थिति किसी एक राष्ट्र या एक नीति की देन नहीं है; यह दशकों से चली आ रही अविश्वास, असमानता और राजनीतिक स्वार्थों की परिणति है। इस बार के संघर्ष ने जिस तरह से निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध चाहे किसी भी नाम पर लड़ा जाए, उसका परिणाम हमेशा मानवीय त्रासदी ही होता है। अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थल-कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते के बाद हमास ने आखिरकार शेष जीवित बचे बीस इस्राइली बंधकों को रिहा कर दिया। जिसके बाद इस्राइल में किसी बड़े उत्सव जैसा जश्न दिखा। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस्राइल-हमास जोखिमभरा युद्धविराम समझौता नाजुक बना हुआ है। इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। इस संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि प्रमुख हितधारकों की ओर से गंभीर एवं ईमानदार प्रयास लगातार होते रहें। वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती भूतहा खण्डहर एवं तबाही में तब्दील हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण की होगी। दो साल से लगातार जारी युद्ध के चलते यह इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है।

एक नाजुक समय में जब युद्धविराम की घोषणा हुई, तो यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि मानवीय विवेक का पुनर्जागरण भी है। यह समझना आवश्यक है कि शांति कोई समझौता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। यही कारण है कि यह युद्धविराम पूरी मानवता के लिए एक 'आशा की किरण' बनकर उभरा है। यह उस संभावना का प्रतीक है कि जब दुनिया के शक्तिशाली देश, विशेषकर अमेरिका, यूरोप, और अरब राष्ट्र अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर मानवीय सरोकारों को महत्व देते हैं, तो समाधान की दिशा में रास्ता बनता है। फिर भी इस शांति की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इस युद्धविराम को अपने कूटनीतिक प्रयासों की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया हो, पर सच यह है कि युद्ध तब रुका जब उसकी भयावहता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। यह विराम किसी की 卐कूटनीति की जीत卐 से अधिक, मानवीय विवशता की उपज है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, मानवीय संगठनों की सक्रियता और आम नागरिकों की पुकार ने मिलकर इस विराम को संभव बनाया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह शांति टिके, युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला फैले। क्योंकि जब तक गाज़ा के लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएँ-पानी, भोजन, दवा, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलते, तब तक शांति केवल कागज़ों पर दर्ज रहेगी। वास्तविक शांति केवल तब संभव है जब अन्याय, दमन और असमानता के ढाँचे टूटें। शांति का अर्थ केवल हथियारों का मौन नहीं, बल्कि हृदयों का परिवर्तन है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए गाजा शांति समझौते को पश्चिम एशिया की ऐतिहासिक सुबह की संज्ञा दी। वे कुछ भी दावा करें, फिलहाल यह कहना कठिन है कि प्रमुख मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार होंगे। भले ही ट्रंप यह कह रहे हों कि गाजा शांति समझौते को सभी मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, लेकिन वस्तुस्थिति इससे अलग है। जब यह समझौता सामने आया था, तब उसे समर्थन देने और ट्रंप की प्रशंसा करने वालों में पाकिस्तान भी था, पर अब वह इस समझौते को समर्थन देने से केवल पीछे ही नहीं हट गया, बल्कि उसने अपने यहां ऐसा माहौल बनाया कि उसके विरोध में कट्टरपंथी तत्व सड़क पर उतर आए। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने गाजा शांति समझौते को नकारने के लिए ही कट्टरपंथी तत्वों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया और फिर उन पर गोलियां भी चलवाईं, ताकि दुनिया और विशेष रूप से अमेरिका को यह संदेश जाए कि उसके लिए गाजा शांति समझौते को स्वीकार करना संभव नहीं। यहां अमेरिका को पाक के दोहरे चरित्र को समझ लेना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अरब लीग और विश्व की सभी बड़ी शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे इस युद्धविराम को केवल घोषणा भर न रहने दें। उसे स्थायी बनाने के लिए एक ठोस मानवीय पुनर्निर्माण योजना तैयार की जाए, जिसमें राजनीतिक समाधान, मानवीय सहायता और संवाद-तीनों को समान महत्व मिले। गाज़ा के बच्चे जब फिर से स्कूलों में लौटेंगे, जब शरणार्थी अपने घरों में बस सकेंगे, जब भय की जगह भरोसा जन्म लेगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि गाज़ा में शांति आई है। इजरायल को यहां ज्यादा उदारता का परिचय देना होगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत ताकतवर है। हमास को भी हिंसा से बचना चाहिए। द्वि-राष्ट्रीय व्यवस्था को जमीन पर ठीक से साकार करना हमास का लक्ष्य होना चाहिए । हमास को अपनी छवि सुधारने की चिंता करनी चाहिए, अगर उस पर यकीन किया गया है, तो उसे खरा उतरना होगा। गाजा में किसी भी सूरत में हिंसा की वापसी नहीं होनी चाहिए। आज यह युद्धविराम भले ही 'एक आशा की किरण' बना हो, परंतु उसे स्थायी प्रकाश में बदलना विश्व समुदाय के विवेक, संवेदनशीलता और सतत प्रयास पर निर्भर करता है।

संपादकीय

भविष्य की बीमार बुनियाद

यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है कि एक लाख से अधिक स्कूलों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के हालिया आंकड़े बताते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में एक लाख चार हजार स्कूल ऐसे थे, जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेल, पीटी और योग जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं। सही मायनों में स्कूलों का शिक्षकों की कमी से जूझना शिक्षा विभाग की नाकामी को ही दर्शाता है। यह हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी पर्याय है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की प्रदूषित कार्य संस्कृति का बोध होता है। आखिर क्या वजह है कि देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुर्गम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुंठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या खास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। निकलती है तो पेपर आउट होने की खबरें आती हैं।

समुद्र विज्ञान के इतिहास में महान वैज्ञानिक - ब्योर्न हेलैंड- हैनसेन

(लेखक - संजय गोस्वामी)

16 अक्टूबर 5, उनके जन्मदिन पर विशेष)

ब्योर्न हेलैंड-हैनसेन का जन्म 16 अक्टूबर 1877 को क्रिश्चियनिया, नॉर्वे में हुआ था, और वे एक नॉर्वेजियन समुद्र विज्ञानी थे। आधुनिक समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में नॉर्वे के अग्रणी थे। महासागरों की भौतिक संरचना और गतिकी पर उनके अध्ययन ने समुद्र विज्ञान को एक मुख्यतः वर्णनात्मक विज्ञान से भौतिकी और रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित विज्ञान में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेलैंड-हैनसेन का अधिकांश कार्य बर्गन में हुआ, जहाँ उन्होंने क्रमशः मरीन बायोलॉजिकल स्टेशन के निदेशक, बर्गन संग्रहालय में प्रोफेसर और भूभौतिकीय संस्थान के पहले निदेशक के रूप में कार्य किया, जिसकी स्थापना 1917 में मुख्यतः उनके प्रयासों से हुई थी। वे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मामलों में सक्रिय थे और 1945 में अंतर्राष्ट्रीय भूगणित और भूभौतिकी संघ के अध्यक्ष चुने गए। क्रिश्चियनिया (अब ओस्लो) में जन्मे, उन्होंने शुरुआत में विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही चिकित्सा की ओर रुख कर लिया। जैसा कि उन्होंने बाद में बताया, मुझे आखिरकार एक छात्र जैसा महसूस हुआ। इस दौरान, के.आर. बर्कलैंड ने हाल ही में खोजी गई एक्स-रे पर तीन व्याख्यान दिए। हेलैंड-हैनसेन अपने पूर्व शिक्षक द्वारा दिए गए इन व्याख्यानों में शामिल हुए और बाद में नियमित व्याख्यानों में उनकी सहायता की। 1898 में, वे ट्रोम्सो से नॉर्वे के उत्तरी क्षेत्रों तक पहले ऑरोरा बोरेलिस अभियान में बर्कलैंड के सहायक के रूप में उनके साथ गए। एक बफ़ीले तूफ़ान में जब उनकी उंगलियाँ जम गईं, तो उन्हें वापस लौटना पड़ा और अपनी चिकित्सा की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद, उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन शुरू किया और कोपेनहेगन में मार्टिन नुडसेन के साथ समय बिताया—यह समुद्र विज्ञान से उनका पहला परिचय था। यह सदी के अंत में, समुद्र अध्ययन के तीव्र विकास के दौर में हुआ। 1898 में, विल्हेम बर्कलैंड ने परिसंचरण प्रमेय विकसित किया। 1900 तक, फ्रिड्टजॉफ नानसेन ने नॉर्वेजियन सागर का व्यावहारिक अध्ययन शुरू कर दिया था, जिसमें हेलैंड-हैनसेन उनके सहायक के रूप में कार्यरत थे। 1902 में, दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित हुए- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अन्वेषण परिषद और क्रिस्टियानिया (ओस्लो) में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय प्रयोगशाला दोनों ही नानसेन के नेतृत्व में और वी.डब्ल्यू. एकमैन उनके सहायक के रूप में संचालित होते थे। उसी वर्ष, एकमैन ने पवन-चालित महासागरीय धाराओं पर अपना सिद्धांत प्रकाशित किया, और 1903 में, हेलैंड-हैनसेन ने महासागरीय गतिविधि पर परिसंचरण प्रमेय लागू किया। गतिकीय गणनाओं के उनके सूत्रीकरण ने उन्हें भौतिक समुद्र विज्ञान के इतिहास में एक स्थायी स्थान दिलाया। इस स्तर पर, अत्यधिक सटीक व्यावहारिक अवलोकन आवश्यक थे, जिसके लिए उपकरणों और विधियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक था। हेलैंड-हैनसेन 1902 से 1914 तक बर्गन में अंतर्राष्ट्रीय महासागर अनुसंधान पाठ्यक्रमों में भौतिक समुद्र विज्ञान के लिए उत्तरदायी थे। 1909 में, नानसेन के साथ मिलकर, उन्होंने प्रभावशाली मोनोग्राफ द नॉर्वेजियन सी पूरा किया, जो उनके द्वारा एकत्रित आँकड़ों का एक व्यापक विश्लेषण था। 1906 से, बर्गन संग्रहालय के जैविक केंद्र के निदेशक के रूप में, हेलैंड-हैनसेन ने एक समर्पित अनुसंधान पोत की आवश्यकता को पहचाना। इसके परिणामस्वरूप 1913 में आर्मोर हैनसेन का निर्माण हुआ—एक छोटा जहाज, केवल 76 फीट लंबा, जिसे उनके अपने विचारों के अनुसार डिज़ाइन किया गया था। यह जहाज उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और यहाँ तक कि स्पिट्सबर्गेन में भी संचालित होता था। उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और यहाँ तक कि स्पिट्सबर्गेन के उत्तर में अपनी यात्राओं के दौरान, उन्होंने इन विचारों की सत्यता का प्रदर्शन किया। पिछली गर्मियों तक ये विचार अपने उद्देश्य में सफल रहे, जब उनकी जगह हीलैंड-हैनसेन के नाम पर एक नया संस्थान स्थापित किया गया। उनकी सिफ़ारिश पर, बर्गेंस संग्रहालय ने 1917 में भूभौतिकीय संस्थान की स्थापना की, जिसमें जल विज्ञान, गतिशील मौसम विज्ञान (विल्हेम बर्कनेस के नेतृत्व में) और 1928 से भूचुंबकत्व और ब्रह्मांडीय भौतिकी विभाग स्थापित किए गए। हीलैंड-हैनसेन की पहल के परिणामस्वरूप 1917 में नॉर्वेजियन भूभौतिकीय आयोग और नॉर्वेजियन भूभौतिकीय संघ का भी गठन हुआ। 1928 में, उन्हें बहुत संतुष्टि हुई जब उनका संस्थान एक नए भवन में स्थानांतरित हुआ, जो बर्गन के नागरिकों की ओर से एक उपहार था। नानसेन के साथ उनका सहयोग और घनिष्ठ मित्रता जीवन भर बनी रही। शुरुआत से ही, उन्होंने एकमैन (श्चय्र्ह्र) के साथ काम किया, विशेष रूप से लंगर डाले हुए जहाजों से धाराओं को मापने वाले प्रयोगों पर, जैसा कि कई प्रकाशित शोधपत्रों से प्रमाणित होता है। एकमैन का अर्थ स्वीडिश समुद्र विज्ञानी वैगन वालफ्रिड एकमैन है, जो समुद्री धाराओं और एकमैन सर्पिल/परत/परिवहन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने 1923 और 1924 में नॉर्वेजियन सागर में आर्मोर हैनसेन पर सवार होकर, और 1930 में कैनरी द्वीप समूह, मदीरा, जिब्राल्टर और पुर्तगाल के बीच के जलक्षेत्र में भी यात्राएँ कीं। बाद के अभियान के निष्कर्ष उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले एकमैन (श्चय्र्ह्र) द्वारा प्रकाशित किए गए थे। अपने शुरुआती वर्षों में, हेलैंड-हैनसेन समुद्र विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में रुचि रखते थे, और उनके कई शोधपत्र जैविक और मत्स्य पालन संबंधी मुद्दों पर केंद्रित थे। हालाँकि, उनका मुख्य ध्यान समुद्री भौतिकी पर था। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में, वे अंतर्राष्ट्रीय भूगणित और भूभौतिकी संघ में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की तुलना में कम सक्रिय थे, जहाँ उन्होंने कई समिति पदों पर कार्य किया, जिनमें भौतिक समुद्र विज्ञान संघ और समुद्र विज्ञानी संघ के अध्यक्ष पद शामिल थे। जब 1930 में बर्गन में क्रिस मिशेलसन संस्थान की स्थापना हुई, तो इसकी योजनाएँ क्रिस मिशेलसन ने हेलैंड-हैनसेन के साथ मिलकर सावधानीपूर्वक तैयार कीं, जो 1955 तक इसके निदेशक रहे। इस विज्ञान और बौद्धिक स्वतंत्रता संस्थान के व्यापक हितों ने हेलैंड-हैनसेन को अपने अंतिम वर्षों में बहुत आकर्षित किया और समय के साथ यह उनका मुख्य ध्यान केंद्रित बन गया। इस स्वाभाविक विकास, उनके सौम्य संवादात्मक व्यवहार और असाधारण व्यक्तिगत आकर्षण के कारण उन्हें सामाजिक और बौद्धिक जीवन में कई भूमिकाएँ सौंपी गईं। उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें कई उपाधियाँ, पदक और अन्य सम्मान प्राप्त हुए।

अपूर्णता से पूर्णता की ओर

मनुष्य का बाह्य जीवन वस्तुतः उसके आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिम्ब मात्र होता है। जैसे ड्राइवर मोटर की दिशा में मनचाहा बदलाव कर सकता है। उसी प्रकार, जीवन के बाहरी ढर्रे में भारी और आश्चर्यकारी परिवर्तन हो सकता है। वाल्मीकि और अंगुलिमाल जैसे भयंकर डाकू क्षण भर में परिवर्तित होकर इतिहास प्रसिद्ध संत बन गये। गणिका और आम्रपाली जैसी वीरांगनाओं को सती-साध्वी का प्रातः स्मरणीय स्वरूप ग्रहण करते देर न लगी। वामित्र और भतृहरि जैसे विलासी राजा उच्च कोटि के योगी बन गये। नृशंस अशोक बौद्ध धर्म का महान प्रचारक बना। तुलसीदास की कामुकता का भक्ति भावना में परिणत हो जाना प्रसिद्ध है। ऐसे असंख्य चरित्र इतिहास में पढ़े जा सकते हैं। छोटी श्रेणी में छोटे-मोटे आश्चर्यजनक परिवर्तन नित्य ही देखने को मिल सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि जीवन का बाहरी ढर्रा जो चिर प्रयत्न से बना हुआ होता है, विचारों में भावनाओं में परिवर्तन आते ही बदल जाता है। मित्र को शत्रु बनते, शत्रु को मित्र रूप में परिणत होते, दुष्ट को संत बनते, संत को दुष्टता पर उतरते, कंजूस को उदार, उदार को कंजूस, विषयी को तपस्वी, तपस्वी को विषयी बनते देर नहीं लगती। आलसी उद्योगी बनते हैं और उद्योगी आलस्यग्रस्त होकर दिन बिताते हैं। दुगरुणियों में सद्गुण बढ़ते और सद्गुणी में दुगरुण उपजते देर नहीं लगती। इसका एकमात्र कारण इतना ही है कि उनकी विचारधारा बदल गई, भावनाओं में परिवर्तन हो गया। संसार का जो भी भला-बुरा स्वरूप हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, समाज में जो कुछ भी शुभ-अशुभ दिखाई पड़ रहा है, व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उत्कृष्ट-निकृष्ट है, उसका मूल कारण उसकी अंतःस्थिति ही होती है। धनी-निर्धन, रोग-नीरोग, अकाल मृत्यु-दीर्घ जीवन, मूर्ख-विद्वान, घृणित-प्रतिष्ठत और सफल-असफल का बाहरी अंतर देखकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यह बाहरी भली-बुरी परिस्थितियां मनुष्य के मनोबल, आस्था और अंतःप्रेरणाओं की प्रतीक हैं।

भाग्य यदि कभी कुछ करता होगा तो निश्चय ही उसे पहले मनुष्य की मनोरुचि में ही प्रवेश करना पड़ता होगा, जिसकी अंतःगतिविधियां सही दिशा में चलने लगीं हैं। किंतु जिसका मानसिक स्तर चंचलता, अवसाद, अवास, आलस्य, आवेश, दैन्य आदि से दूषित हो रहा है, उसके लिए अच्छी परिस्थितियां और अच्छे साधन उपलब्ध होने पर भी दुर्गति का ही सामना करना पड़ेगा।

विचार मंथन

देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्तः लोकतंत्र की जड़ों की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम

(लेखक - सनत जैन)

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर जो सख्त रुख अपनाया है, वह भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए यानी राजद्रोह कानून से संबंधित याचिकाओं को पाँच जजों की संविधान पीठ को भेजने का जो निर्णय लिया है, वह केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। राजद्रोह कानून की उत्पत्ति औपनिवेशिक शासन में हुई थी। अंग्रेजों ने 1870 में इसे इसलिए बनाया था ताकि भारत में स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारियों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को कुचल सके। इस कानून के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी अभियुक्त बनाए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उम्मीद जागी थी कि इस काले कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अफसोस कि यह आज तक जीवित है, और कई बार तो यह उस रूप में भी नजर आया, जो लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत है। आज़ादी के बाद से ही यह कानून सरकारों के हाथों में एक ऐसा औज़ार बन गया, जिसका इस्तेमाल विरोधी विचारों को कुचलने में हुआ। चाहे पत्रकार हों, मानवाधिकार कार्यकर्ता या आम नागरिक हों, किसी भी असहमतिपूर्ण आवाज़ को 'राष्ट्रविरोधी' कहकर निशाना बनाया जा सकता था। इसी मनमाने इस्तेमाल पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जब यह कानून औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है, तो इसे क्यों बनाए रखा जाए। लेकिन सरकार ने अब 'भारतीय न्याय संहिता' (बीएनएस) के ज़रिए उसी कानून को नए नाम और थोड़े बदले हुए शब्दों में फिर से पेश कर दिया। अब इसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध कहा गया है। हालांकि 'राजद्रोह' शब्द हटा दिया गया, लेकिन इसकी भावना लगभग वैसी ही बनी हुई है। यानी जो व्यक्ति सत्ता की आलोचना करे या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, उसे अब भी आसानी से देशविरोधी करार दिया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा, कि कानून का दुरुपयोग ऐसा है जैसे किसी को एक लकड़ी काटने की अनुमति देना, और वह धीरे-धीरे पूरा जंगल काट दे। यह टिप्पणी बेहद प्रतीकात्मक है, यह दिखाती है कि यदि नागरिकों की आवाज़ पर नियंत्रण रखने की कानूनी छूट दी जाए, तो धीरे-धीरे लोकतंत्र का पूरा ढांचा खोखला हो जाता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि नए कानून आने से पुराने मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा; यानी उन मामलों में न्यायिक जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती न केवल संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) की रक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने से जीवित रहता है। लोकतांत्रिक समाज में असहमति को अपराध नहीं, बल्कि सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।

यह फैसला मोदी सरकार ही नहीं, बल्कि आने वाली सभी सरकारों के लिए भी एक संदेश है, कि नागरिकों की आवाज़ को कुचलने वाले औपनिवेशिक कानूनों की समीक्षा अब टाली नहीं जा सकती। संसद को चाहिए कि वह इस दिशा में गंभीरता से विचार करे और ऐसा ढांचा बनाए जिसमें देश की अखंडता की रक्षा हो, लेकिन नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई खतरा न आए। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह रुख लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह केवल एक कानूनी बहस नहीं, बल्कि उस संघर्ष का हिस्सा है जिसमें नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता, कानून और न्यायपालिका, तीनों यह समझें कि असहमति को दबाने से राष्ट्र मजबूत नहीं होता, बल्कि कमजोर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया है कि संविधान की मूल भावना 'हम भारत के लोग' आज भी सर्वोपरि है। देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है। यही वह क्षण है जब न्यायपालिका ने साबित किया है कि वह न केवल कानून की व्याख्या करती है, बल्कि स्वतंत्रता और न्याय की मशाल भी जलाए रखती है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लोगों को मिली खुशखबरी !घटी महंगाई, अमेरिका से ट्रेड डील में हुई प्रगति

आईएमएफ बोले- भारत अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन रहा

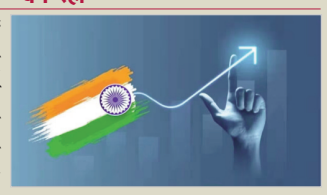

नई दिल्ली बीते दो दिनों में महंगाई में कमी से लेकर विदेशों में भारत की तारीफ की खबरों ने दिल को सुकून दिया। इससे भारत सरकार और देशवासियों को भी बहुत फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि खुदरा महंगाई, यानी सीपीआई, जो आम आदमी की जेब पर असर डालती है, वह गिरकर 1.54फीसदी पर आ गई है। ये जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि खाने-पीने की चीजें, जैसे सब्जियां और अनाज, अब सस्ते हो रहे हैं। अगस्त में ये 2.07फीसदी थी, जो थोड़ा ज्यादा थी। अब बाजार में सामान सस्ता मिलेगा, तो घर चलाना आसान होगा. किसानों को भी खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी/। इसके अलावा थोक महंगाई जो बड़े व्यापारियों और फैक्टरियों के लिए मायने रखती है, वह भी सितंबर में घटकर 0.13फीसदी हो गई। अगस्त में ये 0.52फीसदी थी। सरकार ने बताया कि खाने का सामान, फैक्ट्री के प्रोडक्ट और अन्य चीजों के दाम कम होने से ये राहत मिली है। थोक में सामान सस्ता होने से दुकानों में भी कीमतें कम होंगी, जो अच्छी बात है। वहीं बात भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों की है। दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील रुकी हुई थी, अब उसमें प्रगति दिख रही है। हाल ही में अमेरिकी टीम दिल्ली आई थी, और अब भारतीय दल इसी हफ्ते अमेरिका जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत सही रास्ते पर है और रुके हुए मुद्दे सुलझ सकते हैं। अगर ये डील हो गई, तो भारत का निर्यात बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी और हमारी अर्थव्यवस्था को नया जोश मिलेगा। अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ डील हमारे लिए मौका है। सबसे गर्व वाली खबर आईएमएफ से आई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन रहा है। आईएमएफ-वर्ल्ड बैंक की बैठक से पहले उन्होंने बताया कि भारत की आर्थिक नीतियों ने सबको गलत साबित किया, जो इसकी प्रगति पर शक करते थे। भारत की रफ्तार देखकर दुनिया हैरान है।

सोने,चांदी की कीमतों मे आया अछाल

नई दिल्ली दिवाली करीब आते ही सोना-चांदी की कीमतें आकाश छू रही हैं। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 1,26,697 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी की कीमत 1,60,131 रुपए प्रति किग्रा पर पहुंच गयी है। वहीं गत दिवस दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 2,850 रुपए बढ़कर पहली बार 1.3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के ऊपर पहुंच गयीं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,850 रुपए बढ़कर 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछली सत्र में यह 1,27,950 रुपए पर बंद हुई थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 2,850 रुपए बढ़कर 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इसका पिछला बंद भाव 1,27,350 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 6,000 रुपए के उछाल के साथ 1,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो लगातार पांचवें दिन की बढ़त है। पिछले बाजार सत्र में यह 1,79,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं माना जा रहा है कि सर्राफा कीमतों में तेजी का कारण त्योहारी और शादी-ब्याह के मौसम से पहले मांग बढ़ना है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी भी इसका एक कारण है। ये 12 पैसे गिरकर 88.80 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया पर फिर भी ऊपर बना रहा। वहीं दिन में पहले 4,179.71 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद, यह 0.72 फीसदी बढ़कर 4,140.34 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

टाटा संस आईपीओ लाती है तो ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों को फायदा, बढ़ जाएगा निवेश का मूल्य

नई दिल्ली

अगर टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाती है तो समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों, जिनकी संख्या सात है, को बड़ा फायदा हो सकता है। इससे टाटा संस में उनके निवेश का मूल्य बढ़ जाएगा, जो वर्षों पहले टाटा संस के वर्तमान संभावित मूल्यांकन की तुलना में कम मूल्यांकन पर किया गया था। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसी सूचीबद्ध समूह कंपनियां टाटा संस में शेयरधारकों का तीसरा सबसे बड़ा समूह हैं। ये टाटा ट्रस्ट्स और शापूरजी पलोनजी समूह के बाद आती हैं। इसके अलावा ट्रेंट के पास इस साल मार्च के अंत में टाटा संस में लगभग 1,000 प्रति शेयर के सममूल्य वाले संचयी तरजीही शेयर हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है। समूह की सात सूचीबद्ध कंपनियों की टाटा संस में कुल मिलाकर लगभग 12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा संस में सूचीबद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी उनका ऐसा बड़ा बिना वसूला लाभ है, जिसे टाटा संस के सूचीबद्ध होने पर 'उचित' बाजार मूल्यांकन मिलेगा। सात टाटा ट्रस्टों को संयुक्त रूप से प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके पास टाटा संस की 65.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट क्रमशः 27.98 प्रतिशत और 23.56 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ टाटा संस के दो सबसे बड़े

शेयरधारक हैं। दूसरी ओर, शापूरजी पलोनजी समूह अपनी दो निवेश फर्मों - स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी का मालिक है।

भारत में 1.33 लाख करोड़ निवेश करेगी गूगल

-पहला एआई हब आंध्र प्रदेश में बनाएगी

नई दिल्ली गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस बातचीत के दौरान पिचाई ने पीएम मोदी को बताया कि उनकी कंपनी अगले पांच साल में भारत में 15 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। इस बात की जानकारी पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी। पिचाई ने पीएम मोदी से बातचीत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल के पहले एआई हब का प्लान भी शेयर किया। गूगल ने विशाखापट्टनम में एक बड़ा डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस शुरू करने का ऐलान किया है, जो अमेरिका के बाहर उसका सबसे बड़ा एआई हब होगा। देशभर में विकास को गति देंगे पिचाई ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह हब गीगावाट-स्केल की कंप्यूटिंग कैपेसिटी, एक नए इंटरनेशनल सबमरीन केबल गेटवे और लार्ज स्केल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम भारत में एंटरप्राइजेज और यूजर्स के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे, एआई इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और देशभर में विकास को गति देंगे।

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद सहारा समूह 88 संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज को बेचेगा!

नई दिल्ली सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन अपनी 88 संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की तैयारी में है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सहारा और अडाणी समूह के बीच इस सौदे पर टर्म शीट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह दस्तावेज कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा है। सिब्बल ने कहा कि डील सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी और इससे मिलने वाली रकम सहारा के बकायों से कहीं ज्यादा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा करीब एक लाख करोड़ का हो सकता है। यह रकम सहारा समूह पर निवेशकों के बकाए से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था कि सहारा अपनी दो कंपनियों- सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट के जरिए जुटाई गई रकम को सेबी-सहारा खाते में जमा करे। यह राशि करीब 25,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब तक समूह को करीब 9,481 करोड़ रुपए और जमा करने हैं। इस सौदे से सहारा को बकाया चुकाने और निवेशकों का पैसा लौटाने में बड़ी राहत मिल सकती है। अडाणी समूह की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि समूह इन सभी 88 संपत्तियों को एकमुश्त खरीदने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सौदे की सटीक रकम की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन डील सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही आगे बढ़ेगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी-सहारा खाते से निवेशकों के पैसे की वापसी की प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए यह डील सरकार की जांच के बाद ही आगे बढ़नी चाहिए।

हरे निशान पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार

सेंसेक्स 575 अंक चढ़ा, निफ्टी 25300 के पार

नई दिल्ली

एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी के बीच बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में लिवाली से बुधवार को भारतीय बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने के अंत में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच यह तेजी आई। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में करीब एक प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70 प्रतिशत उछलकर 82,605.43 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 697.04 अंक या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 82,727.02 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 178.05 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,323.55 पर आ गया।

रुपये में आई 75 पैसे की तेजी डॉलर के मुकाबले 75 पैसे की तेजी के साथ 88.06 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो कि लगभग चार महीनों में इसकी सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त है। ऐसा आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप और घरेलू बाजारों में तेजी के कारण हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद के कारण घरेलू बाजार में लगभग 0.70 प्रतिशत की तेजी आई।

सेंसेक्स की कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व सबसे ज़्यादा लाभ में रहीं। एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल और अदानी पोर्ट्स भी लाभ में रहीं। वहीं, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक पिछड़ गए।

यूरोपीय बाजारों में दिखी बढ़त

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग तेजी के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में सकारात्मक रुख रहा।

मंगलवार को अमेरिकी बाजार मिश्रित रुख के साथ बंद हुए। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि दो दिनों की बिकवाली के बाद राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी तेजी आई; फेड अध्यक्ष द्वारा ब्याज दरों पर नरम रुख अपनाने तथा मात्रात्मक सख्ती समाप्त करने पर विचार करने से वैश्विक बाजार में धारणा मजबूत हुई।

रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर सख्ती "चीन बनाम दुनिया" की लड़ाई बना

चीन ने सप्लाई चेन पर किया सीधा हमला, ट्रंप ने दी टैरिफ दोगुना करने की चेतावनी

वॉशिंगटन

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव फिर बढ़ गया है। इसकी वजह चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर सख्त नियम लागू करना। इन मिनरल्स के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर एयरक्राफ्ट तक का उत्पादन करना मुश्किल है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने चीन के इस कदम को उकसाने वाली कार्रवाई बताया है और कहा कि यह अब चीन बनाम बाकी दुनिया की लड़ाई बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 9 अक्टूबर को नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत कोई भी कंपनी चाहे वह चीनी हो या विदेशी यदि उसके उत्पाद में 0.1 फीसदी से ज्यादा रेयर अर्थ मैटेरियल है, तो वह सरकार की अनुमति के बिना निर्यात नहीं करेगी। सैन्य इस्तेमाल के लिए इन खनिजों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चीन इस समय वैश्विक स्तर पर इन खनिजों के 70 फीसदी खनन और 90 फीसदी प्रोसेसिंग करता है। बेसेन्ट ने कहा कि ये खनिज छोटे मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके बिना उत्पादन असंभव है। उन्होंने कहा कि चीन ने सप्लाई चेन पर सीधा हमला किया है, जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत, यूरोप और एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर इसका जवाब देगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ दोगुना करने की धमकी दी है, जो नवंबर से 130

फीसदी तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि चीन की नीतियां बेहद आक्रामक हैं और अमेरिका अपने उद्योगों की रक्षा करेगा। हालांकि बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा- सब ठीक होगा। शी जिनपिंग और मैं दोनों अपने देशों के लिए स्थिरता चाहते हैं। बेसेन्ट ने कहा कि चीन की यह रणनीति उसकी आर्थिक कमजोरी को दर्शाती है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द चर्चाओं से तनाव कम होगा।

इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 की बिक्री में लगातार गिरावट

नई दिल्ली कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 की बिक्री लगातार गिरावट पर है। इस गिरावट के पीछे क्रेटा इलेक्ट्रिक की मजबूत डिमांड है, जिसने आयोनिक 5 की मार्केट पॉपुलैरिटी पर सीधा असर डाला है। सितंबर 2025 में इस एसयूवी की केवल 6 यूनिट बिकीं, जो इस साल की सबसे कमजोर मासिक बिक्री रही। बिक्री आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से सितंबर 2025 के बीच आयोनिक 5 की कुल 135 यूनिट ही बिकी हैं। जनवरी और फरवरी में 16-16 यूनिट, मार्च में 19, अप्रैल में 16, मई में 11, जून में 12, जुलाई में 25, अगस्त में 14 और सितंबर में सिर्फ 6 यूनिट बिकीं। यह आंकड़े साल की दूसरी छमाही में मांग में तेज गिरावट को दिखाते हैं। कई डीलर अब स्टॉक क्लियर करने के लिए 5 लाख से 7 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। आयोनिक 5 की एक्स-शोरूम कीमत रुपए 45.95 लाख है और यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में आती है। इसमें 12.3-इंच की दो डिजिटल स्क्रीन, 6 एयरबैग्स, लेवल-2 एडीएएस और 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल और रीसायकल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से 72.6 केडब्ल्यूएच बैटरी, 631 किलोमीटर की रेंज और 217 एचपी इलेक्ट्रिक मोटर इसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल एसयूवी बनाती है।

रूस से तेल की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की गिरावट होने के बाद भी सबसे बड़ा सप्लायर

नई दिल्ली

भारत के लिए होने वाले तेल की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है इसके बाद भी रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, लेकिन इस साल जनवरी से अगस्त 2025 के बीच रूस से भारत को तेल की आपूर्ति में पिछले साल की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। खबरों के मुताबिक कैपलर के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2025 में भारत ने औसतन 45 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जो अगस्त की तुलना में करीब 70,000 बैरल अधिक था, हालांकि पिछले साल के मुकाबले लगभग समान रहा। इनमें रूस की हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत यानी लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन रही। इंडियन ऑयल कंपनी का कहना है कि भारत की तेल खरीद पूरी तरह आर्थिक गणना पर आधारित होती है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर। उन्होंने कहा कि भारत वही तेल खरीदता है जो कीमत और गुणवत्ता के लिहाज से लाभकारी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन (अक्टूबर से दिसंबर) में ईंधन की मांग बढ़ने के साथ भारत फिर से रूसी तेल आयात बढ़ा सकता है, क्योंकि यह अब भी उच्च गुणवत्ता और बेहतर लाभ दर के चलते सबसे किफायती विकल्प बना हुआ है। हालांकि अमेरिका लगातार भारत पर रूसी तेल की खरीद घटाने का दबाव बना रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुसार निर्णय लेगा। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, रूस से आयात में कमी अमेरिकी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि रूसी

डिस्काउंट घटने, वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव, और अन्य देशों से सस्ता तेल मिलने के कारण हुई है। हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटी हैं, जिससे रूस की दी जाने वाली छूट घटकर सिर्फ 2 डॉलर प्रति बैरल रह गई है, जबकि पहले यह कहीं अधिक थी।

जापानी कंपनी निसान इंडिया की बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें

नई दिल्ली

जापानी कंपनी निसान इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सितंबर 2025 में लगातार चौथे महीने एक्स-ट्रेल की एक भी यूनिट नहीं बिकी। यह स्थिति कंपनी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कंपनी की किफायती एसयूवी मैग्नाइट ही फिलहाल उसकी बिक्री को संभाले हुए है, जबकि प्रीमियम एसयूवी निसान एक्स-ट्रेल की स्थिति लगातार खराब हो रही है। करीब रुपए 49.92 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर पेश की गई यह 7-सीटर लग्जरी एसयूवी एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, लेकिन ग्राहकों से इसे अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी और फरवरी 2025 में एक्स-ट्रेल की एक भी यूनिट नहीं बिकी थी, मार्च में 15 यूनिट, अप्रैल में 76 और मई में 20 यूनिट की बिक्री हुई। इसके बाद जून से सितंबर तक बिक्री का आंकड़ा फिर शून्य पर लौट आया। यानी पूरे साल में अब तक केवल 111 यूनिट ही बिक पाईं, जो भारतीय बाजार में इसके कमज़ोर प्रदर्शन को दर्शाता है। एक्स-ट्रेल डी1 सेगमेंट की प्रीमियम एसयूवी है, जिसमें 7 एयरबैग, 4 डब्ल्यूडी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका हाइब्रिड वर्जन लोकप्रिय है, लेकिन भारत में इसकी ऊंची कीमत, सीमित डीलर नेटवर्क और ब्रांड की कमजोर मौजूदगी इसके लिए बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि निसान ने लंबे समय से भारतीय बाजार में नए मॉडल लॉन्च नहीं किए, जिससे ब्रांड कनेक्ट कमजोर हो गया है। साथ ही, कंपनी की मार्केटिंग और सर्विस रणनीति भी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कमजोर रही है।

यूएई का एमिरेट्स एनबीडी बैंक भारतीय प्राइवेट बैंक आरबीएल को खरीदेगा

इस रणनीति का उद्देश्य आरबीएल बैंक की पूंजी संरचना को मजबूत बनाना

नई दिल्ली

भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूसरे सबसे बड़े बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी, भारतीय प्राइवेट बैंक आरबीएल बैंक को खरीदने की प्रक्रिया में है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक आरबीएल में करीब 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अंतिम चरण की बातचीत कर रहा है। इस निवेश के पूरा होने पर यूएई बैंक आरबीएल बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा और उसका नियंत्रण अपने हाथों में लेगा।

यह बड़ा निवेश प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए किया जाएगा, जिसमें एमिरेट्स एनबीडी बैंक आरबीएल बैंक के शेयर और वॉरंट्स खरीदेगा। इसके बाद, अतिरिक्त 26फीसदी शेयरों के लिए एक ओपन ऑफर भी लाया जाएगा। इस रणनीति का उद्देश्य आरबीएल बैंक की पूंजी संरचना को मजबूत बनाना है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। वर्तमान में आरबीएल बैंक का मार्केट कैप करीब 17,786.8 करोड़ है। निवेश पूरा होने के बाद एमिरेट्स एनबीडी बैंक आरबीएल बैंक की कुल इक्विटी का 51 फीसदी अपने नाम कर लेगा, जिससे उसे बैंक के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण मिल जाएगा। सूत्रों की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में इस सौदे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे एमिरेट्स एनबीडी बैंक की भारत में उपस्थिति और भी मजबूत होगी। यह डील न केवल बैंकिंग सेक्टर में यूएई बैंक की पकड़ बढ़ाएगी, बल्कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच बढ़ते रेमिटेंस मार्केट में भी उसकी स्थिति को सशक्त करेगी। खाड़ी देशों में बसे भारतीय प्रवासी देश के कुल प्रवासी समुदाय का करीब आधा हिस्सा हैं। आरबीआई आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में खाड़ी से भारत आए कुल 38.7 अरब डॉलर के रेमिटेंस में से आधा हिस्सा सिर्फ यूएई से आया था। यह भारत के लिए विदेशी मुद्रा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में एमिरेट्स एनबीडी बैंक का आरबीएल बैंक में निवेश, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को भी नई दिशा देगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने की सरकार से स्थायी प्रतिष्ठान नियमों की समीक्षा की मांग

मकसदः टैक्स प्रणाली को प्रतिस्पर्धी बनाना ताकि चीन जैसे देशों से मुकाबला कर सकें

नई दिल्ली

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने सरकार से स्थायी प्रतिष्ठान नियमों की समीक्षा करने की मांग की है, ताकि टैक्स प्रणाली को प्रतिस्पर्धी बना सकें और देश चीन और वियतनाम जैसे देशों के साथ बेहतर मुकाबला कर सके। भारतीय सेल्युलर और इलेक्ट्रॉनिक्स संघ (आईसीईए) ने कहा है कि इन देशों ने पिछले दशक में अपने नियमों को इस तरह तैयार किया है कि विदेशी कंपनियों की मौजूदगी टैक्स योग्य बनी रहे, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर असर न पड़े। आईसीईए में ऐपल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओप्पो और डिक्सन जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसपर पहले से ही विचार कर रही है। नीति आयोग ने हाल ही में विदेशी निवेशकों के लिए भारत में स्थायी प्रतिष्ठान और लाभ आवंटन में निश्चितता, पारदर्शिता और एकरूपता बढ़ाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन उत्पादन की ग्रोथ निर्यात पर आधारित है, इसलिए टैक्स नियमों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्यात पर बोझ न पड़े और भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। आईसीईए के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन अब 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें से 64 अरब डॉलर सिर्फ स्मार्टफोन उत्पादन का है। पिछले दशक में स्मार्टफोन निर्माण 20 गुना बढ़ा है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसका निर्यात 24 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कप्तान शुभमन सहित भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हुई, विराट और रोहित भी थे टीम के साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हुई। इसमें नये एकदिवसीय कप्तान शुभमल गिल के अलावा अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित कई अन्य खिलाड़ी शामिल थे। भारत के ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से सीरीज शुरु होगी। इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें तीन मैच की एकदिवसीय सीरीज के अलावा 5 मैच की टी20 सीरीज भी खेलेगी। इस दौरे पर एकदिवसीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे जबकि टी20 की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास रहेगी। रोहित और विराट एकदिवसीय सीरीज से सात माह बाद मैदान में वापसी करेंगे।

रवाना होने वाले खिलाड़ियों में कप्तान शुभमन , रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा आदि थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एकदिवसीय मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से ही ये भारतीय टीम की पहली एकदिवसीय सीरीज होगी।

भारत की एकदिवसीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (वीसी), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।

भारत की टी20 टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

एकदिवसीय सीरीज कार्यक्रम-

पहला एकदिवसीय- 19 अक्टूबर; सुबह 9 बजे
दूसरा एकदिवसीय- 23 अक्टूबर; सुबह 9 बजे
तीसरा एकदिवसीय- 25 अक्टूबर; सुबह 9 बजे

टी20 कार्यक्रम

पहला टी20- 29 अक्टूबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से
दूसरा टी20- 31 अक्टूबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से
तीसरा टी20- 2 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से
चौथा टी20- 6 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से
पांचवां टी20- 8 नवंबर; दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से

राशिद खान ने रचा इतिहास, बने दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। अफगानिस्तान के स्टार लेग-स्पिनर राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी वनडे गेंदबाज़ी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। राशिद ने सीरीज में कुल 11 विकेट झटके, जिसमें एक पांच विकेट हॉल (फाइव-विकेट हॉल) भी शामिल था।

इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज, श्रीलंका के महेश थीक्षाना, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, भारत के कुलदीप यादव और नामीबिया के बर्नार्ड स्कॉल्ट्ज़ को पछाड़कर शीर्ष स्थान अपने नाम किया।

राशिद खान का प्रदर्शन

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान अबू धाबी में बांग्लादेश पर 3-0 की जीत के बाद वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। राशिद ने सीरीज में 6.09 की औसत और 2.73 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए।

अफगान खिलाड़ियों का दबदबा

राशिद के साथी अजमतुल्लाह ओमरजई ने भी सीरीज़ में 7 विकेट झटके और आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। वहीं इब्राहिम जद्रान, जिन्होंने लगातार दो मैचों में 95-95 रन की शानदार पारियां खेलीं, वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

जद्रान को सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। उन्होंने कहा, 'सेंचुरी से चूकना थोड़ा दुखद था, लेकिन मैं टीम के लिए 100त्न देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। राशिद और पूरी टीम ने इस जीत को खास बना दिया।'

भारत के लिए अच्छी खबर

वहीं भारतीय क्रिकेटरों की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिला है। कुलदीप यादव सात स्थान की छलांग लगाकर आईसीसी टेस्ट गेंदबाज़ी रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

महिला विश्व कप : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए भारत पर जुर्माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। विशाखापत्तनम में रविवार (12 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए भारत पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। गत चैंपियन टीम ने भारत के 330 रनों के लक्ष्य को एक ओवर और तीन विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पाया गया कि भारत अपने लक्ष्य से एक ओवर पीछे था। यह जुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के मिशेल पेरेरा ने लगाया। खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.22 के अनुसार - जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है - खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया, जिसका अर्थ है कि किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी। यह आरोप मैदानी अंपायर सू रेडफर्न और निमाली परेरा, तीसरे अंपायर किम कॉटन और चौथे अंपायर जैकलीन विलियम्स द्वारा लगाया गया था।

आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में रुट , एकदिवसीय में शुभमन व टी20 में अभिषेक शीर्ष पर

दुबई (एजेंसी)। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को तीनों प्रारूपों टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 के लिए खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की। इसमें टेस्ट बल्लेबाजी में इंग्लैंड के जो रुट शीर्ष पर है। वहीं एकदिवसीय बल्लेबाजी में भारत के शुभमन गिल जबकि टी20 में अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं। गेंदबाजों में भारत के जसप्रीत बुमराह टेस्ट जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान एकदिवसीय में नंबर एक पर हैं। भारत के ही वरुण चक्रवर्ती टी20 रैंकिंग में नंबर एक पर हैं। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लंबी छलांग लगाकर जहां टेस्ट फॉर्मेट में पांचवें स्थान पर पहुंचे हैं, वहीं अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान आठ स्थान की छलांग लगाते हुए एकदिवसीय रुप में दूसरे नंबर के बल्लेबाज बने हैं। शीर्ष पर शुभमन हैं। टी20 में भारत के अभिषेक शर्मा तो गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं।

टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग

1. जो रूट (इंग्लैंड), 2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड), 3. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), 4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), 5. यशस्वी जायसवाल (भारत), 6. टेंबा बवुमा (दक्षिण अफ्रीका), 7. कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका), 8. ऋषभ पंत (भारत), 9. डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड), 10. बेन डकेट (इंग्लैंड)

एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग

1. शुभमन गिल (भारत), 2. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान), 3. रोहित शर्मा (भारत), 4. बाबर आजम (पाकिस्तान), 5. विराट कोहली (भारत), 6. डेरिल मिचेल (भारत), 7. चरिथ असालंका (श्रीलंका), 8. हैरी टैक्टर (आयरलैंड), 9. श्रेयस अय्यर (भारत), 10. शाई होप (वेस्टइंडीज)

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग

1. अभिषेक शर्मा (भारत), 2. फिल साल्ट (इंग्लैंड), 3. तिलक वर्मा (भारत), 4. जोस बटलर (इंग्लैंड), 5. पथुम निसांका (श्रीलंका), 6. ट्रेविस हेड (श्रीलंका), 7. टिम सिफर्ट (न्यूजीलैंड), 8. सूर्यकुमार यादव (भारत), 9. कुसाल परेरा (श्रीलंका), 10. मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया)

टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग

1. जसप्रीत बुमराह (भारत), 2. कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका), 3. मैट हेनरी (न्यूजीलैंड), 4. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया), 5. जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया), 6. नोमान अली (पाकिस्तान), 7. स्कॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया), 8. नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया), 9. मार्को यानसेन (दक्षिण अफ्रीका), 10. मिचेल स्टॉर्क (ऑस्ट्रेलिया)

एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग

1. राशिद खान (अफगानिस्तान), 2. केशव महाराज (दक्षिण अफ्रीका), 3. महिश तिक्षाणा (श्रीलंका), 4. जोफा आर्चर (इंग्लैंड), 5. कुलदीप यादव (भारत), 6. बर्नार्ड स्कोल्ट्ज (नामीबिया), 7. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड), 8. आदिल राशिद (इंग्लैंड), 9. मैट हेनरी (न्यूजीलैंड), 10. रवींद्र जडेजा (भारत)

टी20 गेंदबाजी रैंकिंग

1. वरुण चक्रवर्ती (भारत), 2. अकील हुसैन (वेस्टइंडीज), 3. राशिद खान (अफगानिस्तान), 4. एडम जांपा (ऑस्ट्रेलिया), 5. जैकब डफी (न्यूजीलैंड), 6. आदिल रशीद (इंग्लैंड), 7. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका), 8. अबरार अहमद (पाकिस्तान), 9. नुवान तुषारा (श्रीलंका), 10. कुलदीप यादव (भारत)

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में इंपेक्ट प्लेयर रहे सिराज

नई दिल्ली । वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत के बाद इंपैक्ट प्लेयर का अवार्ड तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिला है। बीसीसीआई ने इस पदक समारोह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। सिराज इस वीडियो में कह रहे हैं, 'यह सीरीज बहुत अच्छी रही क्योंकि हम अहमदाबाद में खेले थे, जहां तेज गेंदबाज़ों को काफी मदद मिली थी पर फिर हम दिल्ली आ गए, और हमें यहां काफी ओवर फेंकने पड़े। हर विकेट 5 विकेट जैसा लगा। एक तेज गेंदबाज के तौर पर, जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है, तो आपको काफी अच्छा अनुभव होता है। आप रेसिंग रूम के प्रभावशाली खिलाड़ी भी होते हैं, इसलिए ये सब बहुत अच्छा लगता है।

उन्होंने आगे कहा, जब आप कुछ हासिल करते हैं, तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने पर बहुत गर्व है। मैं इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखूंगा, क्योंकि मेरा पसंदीदा प्रारुप टेस्ट क्रिकेट है। इसमें कई चुनौतियां होती हैं। आपको पूरे दिन शारीरिक और मानसिक रूप से मैदान पर टिके रहना होता है। मुझे योगदान देने में सक्षम होने पर बहुत गर्व है। सिराज अब ऑस्ट्रेलिया दौरे में खेलते नजर आयेंगे।

नीतीश को लेकर अश्विन ने चयन समिति पर निशाना साधा

-बोले, गेंदबाजी नहीं करानी थी तो किसी और को रखते

नई दिल्ली । भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के मामले को लेकर चयन समिति पर निशाना साधा है। अश्विन ने कहा कि जब नीतीश से गेंदबाजी ही नहीं करानी तो उन्हें टीम में शामिल ही क्यों किया गया था। अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में नीतीश को अंतिम ग्यारह में रखे जाने के कारणों पर भी सवाल उठये हैं। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने कहा भी था कि इस ऑलराउंडर को इसलिए रखा गया जिससे कि उसे अभ्यास का अवसर मिले सकें क्योंकि विदेशी पिचों पर भारत को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की जरूरत होती है। वहीं कोच गौतम गंभीर ने भी कहा कि नीतीश को टीम में रहने से अनुभव तो हो रहा है। दूसरी ओर अश्विन का कहना है कि जब उसे गेंदबाजी ही नहीं दी गयी तो अंतिम ग्यारह में रहने से किस प्रकार से अनुभव मिलेगा। गौरतलब है कि नीतीश ऑलराउंडर के तौर पर दोनों ही मैचों में रखे गये थे। पहले टेस्टम में उन्होंने केवल 4 ओवर गेंदबाजी की, जबकि दूसरे टेस्ट में एक ओवर भी नहीं फेंका था। इसी को लेकर अश्विन ने कहा कि जब रेड्डी से गेंदबाज करानी ही नहीं थी तो उनकी जगह पर किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को खिलाया जा सकता था। या फिर अक्षर पटेल जैसे स्थापित ऑलराउंडर को रखा जा सकता था। अश्विन ने कहा, अगर नीतीश रेड्डी की यही भूमिका है तब तो मुझे लगता है कि आप एक विशेषज्ञ बल्लेबाज या गेंदबाज को खेला सकते हैं। आप अक्षर पटेल को खिला सकते थे।

एशिया कप तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

जोहोर (मलेशिया) (एजेंसी)। मलेशिया के जोहोर बाहरू में सुल्तान ऑफ जोहोर कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जूनियर हॉकी मैच मंगलवार को राष्ट्रगान के बाद दोनों पक्षों के खिलाड़ियों के बीच हाई-फाइव के साथ शुरू हुआ और 3-3 से ड्रॉ रहे कड़े मुकाबले के बाद हाथ मिलाने के साथ समाप्त हुआ।

यह घटनाक्रम पिछले महीने हुए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के विपरीत है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान पर किसी भी तरह की बातचीत से परहेज किया था। एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ पारंपरिक हाथ मिलाने से परहेज किया और अपनी जीत पहलगाम आतंकवादी हमले से प्रभावित परिवारों को समर्पित की। बाद में भारत ने PCB और ACC प्रमुख मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

सूर्यकुमार ने कहा था, 'मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। दिल्ली अभी बहुत दूर है। मुझे नहीं पता कि अगले मैच में पाकिस्तान के साथ क्या होगा। वैसे भी, हम सिर्फ बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ही खेलते हैं, लेकिन उस समय जो भी होगा, हम देखेंगे। फिलहाल, यही वो पल है जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं।'

इसके विपरीत भारत और पाकिस्तान की जूनियर टीमों के बीच सुल्तान जोहोर कप हॉकी मैच का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था। राष्ट्रगान के बाद खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिए और 3-3 से रोमांचक ड्रॉ के बाद हाथ मिलाए। मैच से पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने कथित तौर पर अपने खिलाड़ियों को किसी भी तरह के टकराव से बचने और पूरी तरह से खेल पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था - इस कदम से मैदान पर माहौल सम्मानजनक और खेल भावना से भरा रहा।

ऑस्ट्रेलिया में रोहित और विराट के खेल का जादू देखना चाहते हैं सभी : शुभमन

मुम्बई । अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब सात महीने के बाद मैदान पर खेलते नजर आयेंगे। ये दोनो ही भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए हैं। टीम के रवाना होने से पहले एकदिवसीय प्रारुप के नये कप्तान बने शुभमन गिल ने कहा कि सभी लोग इन दोनो अनुभवी खिलाड़ियों के कौशल को देखना चाहते हैं। शुभन ने कहा कि टीम चाहती है कि दोनों खिलाड़ी अपने खेल का जादू सभी को दिखाएं। गिल ने कहा, ये दोनो ही पिछले एक दशक से अधिक समय से भारतीय टीम को जीत दिलाते रहे हैं। साथ ही कहा कि उनका अनुभव हर कप्तान और हर टीम के लिए बेहद अहम होता रहा है। ऐसे में हम बस यही चाहते हैं कि वो जाएं और अपना कमाल दिखाएं। साथ ही कहा कि भारतीय टीम पिछले दो-तीन साल से एकदिवसीय प्रारुप में बेहतरीन खेल दिखा रही है। इसी लय में वह बनाये रखना चाहती है। उन्होंने कहा, हमने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। टीम लगभग वही है, इसलिए किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा ही रोमांचक होता है और इसी को लेकर हम सब बेहद उत्साहित हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं कई दिग्गज को मानना है कि इस सीरीज के आधार पर ही रोहित और विराट का आगे का करियर निर्भर करेगा।

शुभमन गिल ने अभी तक कप्तानी के सबसे बुरे दिनों का सामना नहीं किया है: गंभीर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल के लिए कप्तानी के अभी शुरुआती दिन हैं और उन्होंने अभी तक अपने सबसे कठिन दिनों का सामना नहीं किया है। गंभीर ने गिल की दबाव और कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता की तारीफ़ की। गिल ने रोहित शर्मा के स्थान पर भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला में 2-2 से ड्रॉ कर शानदार शुरुआत की।

कप्तानी की शुरुआत और दबाव

गिल का यह पहला पूर्णकालिक टेस्ट कप्तानी कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा। दिल्ली में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सात विकेट से जीत के साथ उन्होंने भारतीय कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीत दर्ज की। गंभीर ने बताया कि गिल ने अपनी टीम को दबाव में भी संभालने की क्षमता दिखाई और यह दिखाया कि वह मुश्किल हालात में भी शांत रह सकते हैं।

गंभीर का समर्थन और मार्गदर्शन

गंभीर ने कहा कि एक कोच के रूप में उनका कर्तव्य है कि वह गिल के कंधों से दबाव और आलोचना को कम करें, बशर्ते गिल टीम के लिए सही निर्णय लें और ड्रेसिंग रूम में ईमानदार और पारदर्शी रहें। उन्होंने कहा, 'अब तक, वह शानदार रहे, पारदर्शी, मेहनती और टीम के हित में निर्णय लेने वाले। एक कोच इससे अधिक क्या उम्मीद कर सकता है?'

इंग्लैंड दौरे में कठिन परीक्षा

गंभीर ने इंग्लैंड दौरे को गिल की कप्तानी की सबसे कठिन परीक्षा बताया। उन्होंने याद किया कि गिल को युवा टीम के साथ एक बेहतरीन इंग्लैंड टीम के सामने खड़ा किया गया। गंभीर ने कहा कि इंग्लैंड में बनाए गए रन महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि दबाव में टीम का नेतृत्व करना असली परीक्षा थी। उन्होंने गिल की नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती की सराहना की।

सफलता के हकदार

गंभीर ने कहा कि गिल ने 25 दिनों के कड़े क्रिकेट के दौरान कभी निराशा या दबाव का संकेत नहीं दिखाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए नेतृत्व किया और टीम को एकजुट रखा। गंभीर के अनुसार, गिल अब और भविष्य में हर सफलता के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी खुद को साबित किया।

आगामी वनडे श्रृंखला की तैयारी

वेस्टइंडीज़ पर टेस्ट सीरीज़ जीत के बाद, गिल अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं। गंभीर ने उम्मीद जताई कि गिल आगामी सीरीज़ में भी दबाव में शांत और प्रभावशाली नेतृत्व दिखाएंगे। गिल के लिए यह नया अनुभव उनकी कप्तानी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

मैक्सवेल की ऑलटाइम एकदिवसीय टीम में छह भारतीय और पांच ऑस्ट्रेलियाई

-इंग्लैंड के एक भी खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एक ऑलटाइम एकदिवसीय टीम चुनी है। इसमें सबसे अधिक छह भारतीय और पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पर हैरानी की बात है कि इंग्लैंड के एक भी खिलाड़ी को इसमें जगह नहीं मिल है। मैक्सवेल की इस टीम में सचिन तेंदुलकर और विराट सहित छह भारतीय खिलाड़ियों को लिया गया है। वहीं रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन सहित पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं। टीम में इंग्लैंड के एक भी खिलाड़ी को जग नहीं मिलना उसकी बेइज्जती माना जा रहा है। सलामी बल्लेबाज के लिए मैक्सवेल ने तेंदुलकर और रोहित को शामिल किया है। वहीं हैरानकी की बात है कि डेविड वॉर्नर, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट को इस टीम में जगह नहीं मिली है। तीसरे नंबर पर मैक्सवेल ने विराट कोहली को शामिल करते हुए उन्हें अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय बल्लेबाज करार दिया।

मैक्सवेल की टीम में पोंटिंग चौथे जबकि माइकल बेवन पांचवें नंबर पर हैं। इस नंबर पर उन्होंने इंग्लैंड के इयोन मोर्गन और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। ऑलराउंडर के लिए मैक्सवेल ने शॉन वॉटसन को रखा है।

वहीं विकेट कीपर के रूप में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेनद्र सिंह धोनी को रखा है। इंग्लैंड के जोस बटलर और ऑस्ट्रेलिया से एडम गिलक्रिस्ट को भी टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं मैक्सवेल ने अपने गेंदबाजी आक्रमण में ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा और जसप्रीत बुमराह को रखा है। स्पिनर के तौर पर अनिल कुंबले को रखा गया है।

फीफा क्वालिफायर में रोनाल्डो ने रचा इतिहास, मेसी से आगे निकले

नई दिल्ली (एजेंसी)। फुटबॉल के महानतम गोलस्कोरर्स में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। हंगरी के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में उन्होंने दो गोल दागकर नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन रोनाल्डो की यह शानदार परफॉर्मेंस चर्चा में रही।

पहले हाफ के 22वें मिनट में रोनाल्डो ने क्लोज रेंज से गोल दागा और अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर करियर का 40वां गोल पूरा किया। इस गोल के साथ उन्होंने ग्वाटेमाला के पूर्व खिलाड़ी कार्लोस रुइज़ (39 गोल) को पीछे छोड़ दिया। पहले हाफ के इंजरी टाइम में उन्होंने एक और गोल कर रिकॉर्ड को 41 तक पहुंचा दिया।

इसके साथ ही रोनाल्डो के नाम अब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप क्वालिफायर गोल (41) हैं – जो उन्हें लियोनेल मेसी (36) से काफी आगे ले जाता है। वहीं मेसी ने अब तक 72 क्वालिफायर मैचों में 36 गोल किए हैं।

रोनाल्डो के नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में कई रिकॉर्ड

सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल- 143
सबसे ज़्यादा मैच (कैप्स)- 215+
यूरोपीय चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल- 14

फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सर्वाधिक गोल करने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो - 41 गोल (51 मैच)
कार्लोस रुइज़ - 39 (47 मैच)
लियोनेल मेसी - 36 (72 मैच)
अली दाई - 35 (51 मैच)
रॉबर्ट लेवानडोव्स्की - 33 (42 मैच)

मैच में 78वें मिनट तक पुर्तगाल 2-1 से आगे था, लेकिन हंगरी के डोमिनिक स्जोबोज़लाइ ने इंजरी टाइम में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। मैच के बाद रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर लिखा – 'हम अपने लक्ष्य के करीब हैं! चलो पुर्तगाल!'

कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने माना कि टीम आखिरी 10 मिनट में मैच को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाई। फिर भी, इस ड्रॉ के बावजूद पुर्तगाल ग्रुप एफ में 10 अंकों के साथ टॉप पर बना हुआ है।

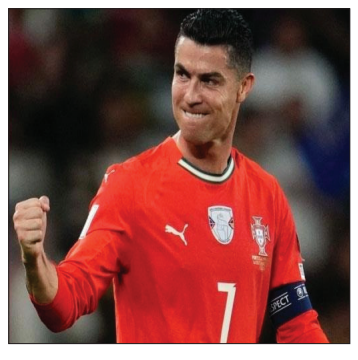

संक्षिप्त समाचार

इस सप्ताह वॉशिंगटन जाएंगे जेलेंस्की

कीव, एजेंसी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरान वे यूएस से लंबी दूरी के हथियारों की संभावित आपूर्ति और अन्य सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि वे कीव को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भेज सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से उनकी मुलाकात शुक्रवार तक हो सकती है। इसके अलावा वे रक्षा और ऊर्जा कंपनियों, साथ ही कांग्रेस के सदस्यों से भी मिलेंगे।

मैक्सिको में भयंकर बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 64

मैक्सिको, एजेंसी। पिछले सप्ताह मैक्सिको में हुई भयंकर बारिशों के कारण मृतकों की संख्या सोमवार तक 64 हो गई, जबकि 65 लोग अभी भी लापता हैं। भारी वर्षा के कारण कई नदियां उफान पर आ गईं और लैंडस्लाइड से कई गांवों का संपर्क कट गया। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम की दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में सिविल डिफेंस कोऑर्डिनेटर लौरा वेलाज़क्वेज़ अल्जुआ ने बताया कि बचाव अभियान अब उन समुदायों तक भी फैलाया जा रहा है, जो पहले पहुंच से बाहर थे।

काठमांडू एयरपोर्ट पर 11 किग्रा से ज्यादा गांजा लेकर तीन भारतीय गिरफ्तार

काठमांडू, एजेंसी। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तीन भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 11 किलो 275 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार भारतीय यात्रियों की पहचान सलीम इब्राहिम अंसारी (50), रेहान मोहम्मद अजाज़ शेख (24) और जैनब बशीर (32) के रूप में हुई है। नेपाल पुलिस के एक बयान के अनुसार, ये तीनों बैंकॉक से एयर एशिया की फ्लाइट से रविवार दोपहर काठमांडू पहुंचे थे। फिलहाल बरामद गांजा और आरोपियों को आगे की जांच के लिए नेपाल पुलिस के नार्कोटिक ड्रग्स ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है।

चीन के दर्जनों भूमिगत चर्च पादरी हिरासत में लिए गए

बीजिंग, एजेंसी। चीन में पुलिस ने देश के सबसे बड़े चर्चों में से 30 भूमिगत पादरियों को हिरासत में लिया गया है। एक चर्च प्रवक्ता और रिश्तेदारों ने बताया कि यह 2018 के बाद से ईसाइयों पर सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले हफ्ते बीजिंग द्वारा दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रणों में नाटकीय रूप से विस्तार करने के बाद चीन-अमेरिका के बीच नए सिरे से तनाव बढ़ने के बीच ये गिरफ्तारियां हुईं। इन गिरफ्तारियों की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने निंदा की और तत्काल रिहाई की मांग की। प्रवक्ता सीन लॉन्ग ने बताया, जायन चर्च के संस्थापक पादरी जिन मिंगरी को दक्षिणी शहर बेइहाई स्थित उनके घर पर हिरासत में लिया गया।

वेनेजुएला में खदान हादसा- भीषण बारिश से सोने की खान धसने से 14 मजदूरों की मौत

काराकास, एजेंसी। वेनेजुएला के दक्षिणपूर्वी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक सोने की खदान धंस गई, जिसमें कम से कम 14 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा एल कालयो कस्बे में हुआ, जो राजधानी कराकस से करीब 850 किलोमीटर दूर स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के शवों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय बचाव दल के अनुसार, गहराई वाले हिस्सों में पानी निकालने के बाद ही अंदर फंसे लोगों की तलाश जारी रखी जाएगी। फिलहाल मौतों की संख्या अन्य खनिकों के बयान के आधार पर बताई गई है।

खैबर पख्तूनख्वा के नए सीएम बने सुहैल विपक्ष का बहिर्गमन

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उम्मीदवार सुहैल अफरीदी को सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का नया मुख्यमंत्री चुना गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सदन से बहिर्मगन किया। प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाती ने विपक्ष के बहिर्गमन के बावजूद मतदान की प्रक्रिया जारी रखी। अफरीदी को 145 में से 90 वोट मिले, जबकि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) बीएमएलएन और पीपीपी के उम्मीदवारों को कोई वोट नहीं मिला। पार्टी के संस्थापक इमरान खान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अफरीदी ने कहा, उन्होंने साधारण से कार्यकर्ता, राजनीति से कोई पारिवारिक संबंध नहीं रखने वाले शख्स को मुख्यमंत्री चुना।

नीदरलैंड्स ने अपने कब्जे में ली चीन की बहुत बड़ी चिप कंपनी, व्यापार युद्ध बढ़ने की आशंका

एम्स्टर्डम, एजेंसी। वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच नीदरलैंड्स सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए चीन की विंगटेक टेक्नोलॉजी के स्वामित्व वाली डच चिपमेकर कंपनी नेक्स्पेरिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। यह कदम डच आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा गुड्स अवेलेबिलिटी एक्ट के तहत उठाया गया है, ताकि देश में आवश्यक चिप्स की सप्लाई और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नेक्स्पेरिया में गंभीर प्रशासनिक खामियों के हालिया और तात्कालिक संकेत मिले हैं, जो नीदरलैंड्स और यूरोप की तकनीकी क्षमताओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि इन क्षमताओं का नुकसान डच और यूरोपीय आर्थिक सुरक्षा के लिए जोखिम साबित हो सकता है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जो चिप्स पर भारी निर्भर करता है।

चिप उद्योग में रणनीतिक हस्तक्षेप : नीजमेगन में मुख्यालय वाली नेक्स्पेरिया दुनिया की प्रमुख चिप निर्माता कंपनियों में से एक है, जो मुख्यतः सरल कंप्यूटर चिप्स (जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर) बनाती है। साथ ही यह कंपनी वाइड गैप सेमीकंडक्टर तकनीक पर भी काम करती है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग सिस्टम्स और एआई डेटा सेंटर्स में होता है। नीदरलैंड्स सरकार का कहना है कि यह हस्तक्षेप अत्यंत असाधारण स्थिति में किया गया है, ताकि आपातकालीन

परिस्थितियों में चिप आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न आए। यह निर्णय सितंबर में लागू किया गया था, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अब की गई है।

अमेरिका-चीन तनाव की पृष्ठभूमि में निर्णय : यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के निर्यात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। हालांकि डच आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने अमेरिकी दबाव से इनकार करते हुए इसे सिर्फ एक संयोग बताया, लेकिन यह निर्णय उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है जिसमें अमेरिका और नीदरलैंड्स दोनों चिप उद्योग पर निर्यात नियंत्रण को लेकर करीबी सहयोग कर रहे हैं।

उधर, बीजिंग ने हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाया है, जो यूरोप के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बेहद अहम हैं। इससे यूरोप-चीन व्यापारिक रिश्तों में और तनाव आ सकता है।

विंगटेक पहले से अमेरिकी निगरानी सूची में : गौरतलब है कि विंगटेक टेक्नोलॉजी को दिसंबर 2024 में अमेरिका ने अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल किया था। आरोप था कि कंपनी संवेदनशील सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताओं वाली संस्थाओं को हासिल करने के चीन सरकार के प्रयासों में सहायता कर रही है।

विंगटेक की तीखी प्रतिक्रिया : इस फैसले पर विंगटेक ने नाराजगी जताई है। कंपनी ने अपने अब हटाए गए वीचैट पोस्ट में डच सरकार के कदम को भू-राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित अत्यधिक हस्तक्षेप बताया। विंगटेक ने कहा कि उसने 2019 में नेक्स्पेरिया के अधिग्रहण के बाद से सभी स्थानीय कानूनों का पालन किया है और उसके यूरोप में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं- जिनमें नीदरलैंड्स, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं। नेक्स्पेरिया की प्रतिक्रिया और प्रभाव नेक्स्पेरिया के प्रवक्ता ने सीएनबीसी से कहा कि कंपनी सभी नियमों का पालन कर रही है और नियमित रूप से अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। इस घोषणा के बाद शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में विंगटेक के शेयर 10% की गिरावट के साथ अपने दैनिक सीमा तक लुढ़क गए। कंपनी की एक कॉर्पोरेट फाइलिंग (13 अक्टूबर) के अनुसार, अब नेक्स्पेरिया अस्थायी बाहरी प्रबंधन के अधीन है, जिसमें एक वर्ष तक कंपनी की परिसंपत्तियों, व्यवसाय या कर्मचारियों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, विंगटेक के चेयरमैन झांग शुएझेंग को नेक्स्पेरिया में उनकी सभी भूमिकाओं से निलंबित कर दिया गया है, हालांकि कंपनी के दैनिक कार्य सामान्य रूप से जारी रहेंगे। इससे पहले 2023 में नीदरलैंड्स सरकार ने नेक्स्पेरिया द्वारा चिप स्टार्टअप एनओडब्ल्यूआई के अधिग्रहण की जांच की थी, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अब यह नया कदम चीन-नीदरलैंड्स व्यापारिक रिश्तों को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब डच कंपनी एएसएमएल को चीन को उन्नत चिप-मेकिंग उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार युद्ध और तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, नीदरलैंड्स सरकार का यह अभूतपूर्व कदम इस बात को रेखांकित करता है।

ट्रंप ने क्लिंटन से मिली सराहना का किया स्वागत, अमेरिकी राष्ट्रपति को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तारीफ का स्वागत किया है। बता दें कि, बिल क्लिंटन ने गाजा युद्धविराम समझौते में ट्रंप की भूमिका की प्रशंसा की थी। ट्रंप ने इसे बहुत अच्छा कहा और माना कि क्लिंटन सच कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उनका बिल क्लिंटन से पुराना संबंध रहा है। उन्होंने कहा, वो मेरे दोस्त रहे हैं ज्वो और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन भी मेरी शादी में भी आए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी टीम, कतर और अन्य देशों ने मिलकर इस समझौते को सफल बनाया। उन्होंने इस मौके को स्थायी शांति की दिशा में एक मौका बताया।

ट्रंप ने गाजा युद्धविराम को लेकर दिया भाषण : गाजा युद्धविराम को लेकर ट्रंप ने मिस्र के शहर शार्म अल-शेख में एक शांति सम्मेलन में भी भाषण दिया। उन्होंने इस समझौते को पश्चिम एशिया के लिए नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा, हमने वो कर दिखाया जो असंभव कहा जा रहा था। अब युद्ध खत्म हो गया है और एक नई सुबह आ रही है।

गाजा के पुनर्निर्माण पर भी बोले ट्रंप : इस दौरान ट्रंप ने दोहराया कि गाजा के पुनर्निर्माण में मदद तो होगी लेकिन पैसा हिंसा के लिए

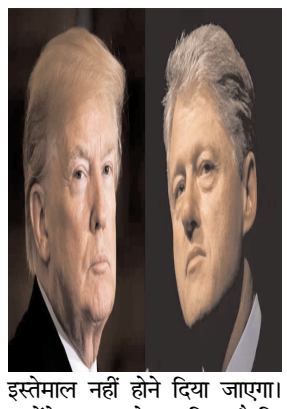

इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमने तय किया है कि गाजा को दोबारा खड़ा करेंगे, लेकिन हथियारबंदी नहीं होने देंगे। मिस्र के शहर शार्म अल-शेख में एक शांति सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी और ट्रंप ने इसकी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन से पहले हमास ने सभी 20 जीवित इस्राइली बंधकों को रिहा कर दिया था।

ट्रंप को मिस्र ने किया सम्मानित, इस्राइल करेगा सम्मान : मिस्र ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। वहीं, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने उन्हें इस्राइल प्राइज के लिए नामित किया और कहा, ट्रंप इस्राइल के अब तक के सबसे बड़े मित्र हैं।

हमास की कैद में एकमात्र हिंदू बंधक बिपिन जोशी की मौत, इजरायल को लौटाया शव

येरुशलम, एजेंसी। हमास की ओर से बंधक बनाए गए नेपाली हिंदू छात्र बिपिन जोशी का शव इजरायल को लौटा दिया गया है। 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर किए गए हमले के दौरान उसका अपहरण कर लिया गया था। अटैक के वक्त जोशी ने अपनी बहादुरी से कई सहपाठियों की जान बचाई थी। सोमवार को गाजा में संघर्ष विराम समझौते के बाद उसकी मृत्यु की पुष्टि ऐसे समय हुई, जब 20 जीवित बंधकों की रिहाई पर उत्सव का माहौल था। बंधक बनाए जाने के कुछ दिनों बाद इजरायली सेना की ओर से वीडियो फुटेज जारी किया गया, जिसमें जोशी को गाजा के शिफा अस्पताल में घसीटते हुए दिखाया गया था। यह उनकी आखिरी ज्ञात जीवित झलक थी। हमास के लड़ाकों ने जब हमला किया, तब 22 वर्षीय बिपिन जोशी नेपाल से गाजा सीमा के पास किबुत्ज अलुमिम गए थे। यहां वह खेती-किसानी को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए आए थे। जोशी गाजा में जीवित माने जाने वाले एकमात्र गैर-इजरायली और हिंदू बंधक थे। नेपाल के इजरायल में राजदूत धन प्रसाद पंडित ने रिपब्लिका को उनकी मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात हमास ने जोशी के शव को इजरयइली अधिकारियों को सौंप दिया। पंडित ने कहा, बिपिन जोशी का शव हमास ने इजरायली अधिकारियों को सौंपा है और इसे तेल अवीव ले जाया जा रहा है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने कहा कि हमास ने बिपिन जोशी सहित 4 बंधकों के शव लौटाए हैं। उनके शव को नेपाल भेजने से पहले डीएनए टेस्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि उनका अंतिम संस्कार नेपाली दूतावास के सहयोग से इजरायल में किया जाएगा। जोशी की इजरायल यात्रा सितंबर 2023 में शुरू हुई, जब वह 16 अन्य छात्रों के साथ किबुत्ज अलुमिम गए थे। यह पहल नेपाली छात्रों को इजरायली कृषि तरीकों के बारे ट्रेनिंग देने के लिए की गई थी। 7 अक्टूबर की सुबह हमास आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। छात्रों ने बम बंकर में शरण ली। जब बंकर के अंदर ग्रेनेड फेंके गए तो जोशी ने एक जिंदा ग्रेनेड को पकड़कर बाहर फेंक दिया, जिससे कई लोगों की जान बच गई।

दुनिया को आपकी जरूरत है, ट्रंप को रिझाने में जुटा पाकिस्तान; फिर अलापा नोबेल राग

इस्लामाबाद, एजेंसी। अमेरिका को रिझाने का पाकिस्तान कोई मौका छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान के चार दिन बाद ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार के लिए फिर नॉमिनेट कर दिया। शरीफ का कहना है कि दुनिया को इस समय सबसे ज्यादा ट्रंप की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में बड़ी भूमिका निभाने का दावा लगातार किया जा रहा है।

गाजा में शांति के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन में शरीफ ने कहा, मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वास्तविक तौर पर लगता है कि वह वास्तविक रूप से सबसे शानदार उम्मीदवार हैं...। मुझे लगता है कि आप वह व्यक्ति हैं, जिसकी

जरूरत इस दुनिया इस समय सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, दुनिया आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगी, जिसने 7 और अब 8 युद्ध रुकवाने के लिए सबकुछ किया।

पाकिस्तान पीएम ने कहा, अगर यह सज्जन नहीं होते, तो कौन जानता है कि क्या होता। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं। अगर यह अपनी शानदार टीम के साथ उन चार दिनों में दखल नहीं देते, तो युद्ध उस स्तर तक पहुंच जाता, जहां कोई भी यह बताने के लिए नहीं बचता कि आखिर क्या हुआ था। ट्रंप की सफाई नोबेल शांति पुरस्कार से चूकने के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष समेत आठ युद्धों को सुलझाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं किया। ट्रंप अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष समेत सात युद्धों को सुलझाने का दावा करते रहे हैं। हालांकि, अब उन्होंने इजराइल-गाजा संघर्ष को जोड़कर यह संख्या आठ कर दी है।

रविवार को अपने एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने की योजना का भी संकेत दिया। ट्रंप ने कहा, यह मेरा आठवां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है, और मैंने सुना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। मैंने कहा, मुझे वापस आने तक इंतजार करना होगा। मैं एक और युद्ध रोक रहा हूं। क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं। मैं शांति स्थापित करने में माहिर हूं। नोबेल विजेता पर भड़का वाइट हाउस वाइट हाउस ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार समिति की आलोचना करते हुए उस पर वैश्विक शांति में ट्रंप के योगदान को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे राजनीति को शांति से अधिक प्राथमिकता देते हैं। यह बात वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद कही गई।

पाकिस्तानी रक्षामंत्री बोले- अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी भरा माहौल है। इस्लामाबाद और काबुल में किसी भी वक्त संघर्ष शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों में कोई झड़प नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध ठंड पड़ गए हैं। आसिफ ने आगे कहा, संघर्ष की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर अफगानिस्तान धमकी देता है, तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानके ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 11 अक्टूबर को देर रात पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया था। सोमवार को बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर रहीं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रियों का आना-जाना बंद रहा। अफगानिस्तान का दावा- 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने शनिवार रात (11 अक्टूबर) को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियां कब्जे में ले लीं। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसके सिर्फ 25 सैनिक मारे गए, जबकि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानआर्मी चीफ और रक्षा मंत्री को वीजा नहीं दिया, 3 बार अर्जी खारिज की अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई प्रमुख असीम मलिक और 2 अन्य जनरलों को वीसा देने से इनकार कर दिया है। टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पिछले 3 दिनों में वीसा अर्जी 3 बार खारिज की गई है। पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया है कि सीमा पर संघर्ष में उसके 23 सैनिक और 200 तालिबानी मारे गए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि 58 पाक सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए हैं। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाक-अफगान संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की है। उधर, भारत के दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीमा संघर्ष में अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इटली की पीएम मेलोनी से कहा- स्मोकिंग छोड़ दो; गाजा पीस समिट में मिले

वाशिंगटन, एजेंसी। तुर्किये के राष्ट्रपति राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा है। दोनों नेताओं ने सोमवार को मिस्र में गाजा पीस समिट में मुलाकात की। इस दौरान एर्दोगन ने कहा, मैंने आपको हवाई जहाज से उतरते देखा। आप शानदार लग रही हैं, लेकिन मुझे आपको स्मोकिंग छोड़वाना होगी। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हंसते हुए कहा कि यह असंभव है। मेलोनी ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि स्मोकिंग छोड़ने से उनकी सामाजिकता कम हो सकती है। मेलोनी ने एक किताब में स्वीकार किया था।

स्पेसएक्स ने 40 माले की इमारत के बराबर रॉकेट का सफल परीक्षण किया, 11वीं उड़ान में हासिल की यह खासियत

वाशिंगटन , एजेंसी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फिर बड़ा कारनामा किया है। सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 11वां टेस्ट सफल रहा। मंगलवार (14 अक्टूबर) को सुबह 5:00 बजे टेक्सास के बोका चिका से स्टारशिप की सफल लॉन्चिंग की गई। स्टारशिप की हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। जो कि टेक्सास के दक्षिणी सिरे से आकाश में गर्जना के साथ उड़ा। बूस्टर रॉकेट अलग हो गया और योजना के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित रूप से प्रवेश किया, और स्टारशिप हिंद महासागर में उतरने से पहले अंतरिक्ष में उड़ता रहा। 11वें परीक्षण का लाइव वीडियो स्टारशिप रॉकेट को परीक्षण उड़ान के दौरान प्रक्षेपित किया और पिछली बार (10वां टेस्ट) की तरह ही दुनिया के आधे हिस्से का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया। बूस्टर ने योजना के अनुसार मेक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित प्रवेश किया, और अंतरिक्ष यान हिंद महासागर में उतरने से पहले अंतरिक्ष में घूमता रहा। घटनास्थल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सुपर हैवी बूस्टर की अमेरिका की खाड़ी में वॉटर लैंडिंग कराई गई, जबकि स्टारशिप की हिंद महासागर में वॉटर लैंडिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट 1 घंटे 6 मिनट का था। स्टारशिप अंतरिक्ष यान (ऊपरी हिस्सा) और सुपर हैवी बूस्टर (निचला हिस्सा) को पूरे तौर से स्टारशिप कहा जाता है। जिसका उद्देश्य भविष्य में रॉकेट को उड़ान भरने वाली जगह पर वापस लाने से जुड़े परीक्षण करना था। स्टारशिप की ऊंचाई 403 फीट है। जिसका उपयोग स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क मंगल ग्रह पर लोगों को भेजने के लिए करना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस भेजने के अपने प्रयासों में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट, स्टारशिप का उपयोग करने की योजना बनाई थी। कंपनी ने उन आलोचकों को भी खारिज करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा था कि इसकी तकनीक नासा की चंद्र परियोजनाओं को पूरा करने और मनुष्यों को मंगल ग्रह पर ले जाने के मस्क के सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।

पहले कनाडा, फिर ब्रिटिश पीएम की बेइज्जती; ट्रंप ने मिस्र में इन नेताओं को किया शर्मसार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं को अनजाने में या जानबूझकर शर्मिंदा कर दिया। यह घटना तब घटी जब ट्रंप ने इजरायल-हमास युद्ध को समाप्त करने वाले ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाए गए वैश्विक नेताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सहित दर्जनों देशों के नेता मौजूद थे। ट्रंप के भाषण और उनके व्यवहार ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा छेड़ दी। कई यूजर्स ने इसे ट्रंप का क्लासिक स्टाइल करार दिया। पहले कनाडा के कार्नी- प्रेसिडेंट कहकर हुई गलती, लेकिन जोक में बदल गया ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जिक्र करते हुए उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कह दिया, जबकि कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। यह गलती ट्रंप के वाइट हाउस में कार्नी से हुई हालिया मुलाकातों के संदर्भ में और भी मजेदार लगी, जहां ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी दी थी। कार्नी ने तुरंत मंच पर हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, आपने मुझे अपग्रेड कर दिया, सर! ट्रंप ने हंसते हुए कहा, ओह, क्या मैंने ऐसा कहा? कम से कम मैंने गवर्नर तो नहीं कहा। दोनों नेताओं के बीच यह आदान-प्रदान कैमरों में कैद हो गया और कार्नी के पीछे खड़े ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने नर्वस स्माइल के साथ तालियां बजाते दिखे। यह घटना ट्रंप-कार्नी संबंधों की पृष्ठभूमि में देखी जा रही है। 7 अक्टूबर को वाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कनाडा पर लगे भारी टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया था। कार्नी पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप की चापलूसी की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने कोई रियायत नहीं दी। ब्रिटिश पीएम स्टार्मर की बेइज्जती-मंच पर बुलाया, लेकिन बोलने

न दिया कार्नी के साथ जोक के ठीक बाद ट्रंप ने मंच पर खड़े नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैंने आप सबको इतने सालों से जाना है। तभी उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की ओर इशारा किया और कहा, कीर, आपका क्या? आइए, बोलिए! स्टार्मर ने समझा कि उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया है, इसलिए वे उत्साहित होकर मंच के आगे बढ़े। लेकिन ट्रंप ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं-नहीं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आपकी बारी बाद में। स्टार्मर असहज दिखे, चारों ओर देखा, फिर धीरे-धीरे पीछे लौटे। कार्नी ने उन्हें हल्के से कंधा थपथपाया, लेकिन स्टार्मर की यह स्क्काटलिंग (पीछे हटना) वाली हरकत कैमरों में कैद हो गई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार्मर ने एक फीकी मुस्कान के साथ स्थिति संभाली, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा, ट्रंप ने स्टार्मर को वर्ल्ड स्टेज पर एपिक तरीके से शर्मिंदा किया। ट्रंप कभी नहीं भूलते! एक अन्य ने कहा, स्टार्मर सोचे होंगे, मैं तो बोलने आया था, लेकिन ट्रंप का जोक बन गए। कई अन्य नेताओं को किया शर्मसार-ऐतिहासिक मध्य पूर्व का उदय भाषण में तंज ट्रंप का भाषण मुख्य रूप से गाजा शांति समझौते पर केंद्रित था, जिसे उन्होंने मध्य पूर्व में ऐतिहासिक सवाना करार दिया। समझौते के तहत इजरायल-हमास के बीच कैदी-बंदी आदान-प्रदान और युद्धविराम पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की। लेकिन भाषण के दौरान ट्रंप ने कई नेताओं पर तंज कसे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी को ट्रंप ने कहा, आपने मिस्र को फिर से महान बनाया, लेकिन मेरी मदद के बिना यह संभव न था। सीसी ने मुस्कुराकर ताली बजाई, लेकिन कुछ विश्लेषकों ने इसे ट्रंप का क्रेडिट चोरी करार दिया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने मेरा पुराना दोस्त कहा, लेकिन ये भी कहा कि तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए थी, वरना यह युद्ध इतना लंबा न चलता। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का असली बॉस कहा, लेकिन तंज कसते हुए बोले, तुम्हारे पैसे से यह डील हुई, लेकिन मेरा दिमाग था। भारत के सवाल पर असहज दिखे शहबाज शरीफ इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कुछ ऐसा पूछ लिया कि वे खुद असहज दिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लिए बिना उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ''भारत महान देश है, जिसका नेतृत्व मेरे बहुत अच्छे मित्र कर रहे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर का केंद्र और संघ पर हमला, आज का दौर 1975 के आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर ने केंद्र और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा माहौल है, जहां स्वतंत्र विचार, आलोचना और सवाल उठाने की क्षमता को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि ÷आज का दौर 1975 के आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, बल्कि आपतकाल को चुपचाप लागू किया गया है।÷

जस्टिस मुरलीधर दिल्ली में आयोजित 'प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा मेमोरियल लेक्चर' में बोल रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने दो टूक कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थान स्वतंत्र नहीं रहे हैं। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में यह अब संस्थान तय नहीं करते कि क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा और किस विषय पर चर्चा की जा सकती है, बल्कि यह फैसले सत्ता और उससे जुड़े बाहरी तंत्र लेते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का भारत वह जगह नहीं रहा, जहां शिक्षण संस्थान स्वतंत्र विचारों की प्रयोगशाला हों। ÷अब फैज अहमद फैज की कविता पढ़ना भी जोखिम भरा हो गया है। आजादी के नारे लगाने वाला छात्र 'अर्बन नक्सल' या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का सदस्य कहला सकता है।

जस्टिस मुरलीधर ने संघ की शिक्षा शाखा 'विद्या भारती' का विशेष उल्लेख कर बताया कि यह संगठन देशभर में एक समानांतर शिक्षा तंत्र खड़ा कर चुका है। उनके अनुसार, विद्या भारती के पास वर्तमान में 12,754 औपचारिक और 12,654 अनौपचारिक स्कूल हैं, जिसमें करीब 77 लाख छात्र और 1.5 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में जो इतिहास और संस्कृति पढ़ाई जा रही है, वह बच्चों के दिमाग में विकृत गौरव और सांप्रदायिक श्रेष्ठता की भावना भर रही है।

उन्होंने चौथी कक्षा की किताब 'बोधमाला चार' का उदाहरण देकर कहा कि उसमें लिखा गया है कि म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका पहले भारत का हिस्सा थे। अगर छोटे बच्चों को यही सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया कभी हमारा हिस्सा थी, तब वे साझेदारी नहीं बल्कि प्रभुत्व की मानसिकता लेकर चलने वाले है। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि अब विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रमों से वे विषय हटाए जा रहे हैं जो सरकारी विचारधारा से मेल नहीं खाते। उन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध लेखक ए.के. रामानुजन का निबंध '300 रामायण' इसलिए हटाया गया क्योंकि वह यह दिखाता था कि रामायण के कई रूप हैं – जो आरएसएस के ÷एक ही सच के एजेंडे के खिलाफ जाता है। उन्होंने 1975 के आपातकाल की तुलना आज की परिस्थितियों से कर कहा, उस समय सेंसरशिप थी, पत्रकारों को जेल में डाला गया था, पर लोग जानते थे कि वे आजादी खो रहे हैं। आज लोग यह

तक नहीं जानते कि वे कब देशद्रोही कहे जाएंगे, कब उनके खिलाफ केस दर्ज होगा या सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चला दी जाएगी। डर अब भीतर तक समा चुका है।

अंत में उन्होंने कहा कि इसतरह के दौर में भी कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। ÷जब हर संस्था को संगठन में बदलने की कोशिश हो रही है, जब अदालतों से लेकर स्कूलों तक राष्ट्रवाद का नया पाठ पढ़ाया जा रहा है, तब यह याद रखना जरूरी है कि असली राष्ट्रभक्ति सत्ता से सवाल पूछना है, उसके आगे झुकना नहीं।

जस्टिस मुरलीधर के इस भाषण ने देश के बौद्धिक वर्ग में नई बहस छेड़ दी है। जहां कई शिक्षाविद और पत्रकार उनकी बातों से सहमत हैं, वहीं सत्तारूढ़ विचारधारा के समर्थक इस राजनीतिक बयान कहकर खारिज कर रहे हैं।

गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व सीएम रवि नाइक का निधन

पणजी गोवा के वरिष्ठ नेता, कृषि मंत्री और दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके रवि नाइक का बुधवार को निधन हो गया। 79 वर्षीय नाइक को घर पर अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वे जीवन की जंग हार गए। रवि नाइक के निधन से गोवा में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को पोंडा स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि गोवा ने एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता खो दिया है। रवि नाइक ने अपना राजनीतिक सफर पोंडा नगर परिषद के पार्षद के रूप में शुरू किया था। वे 1984 में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के टिकट पर पहली बार विधायक बने। वर्ष 1991 में वे पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और करीब 28 महीने तक इस पद पर रहे। इसके बाद 2 अप्रैल 1994 को वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि यह कार्यकाल केवल 6 दिन का रहा। नाइक ने अपने राजनीतिक जीवन में कई दलों का दामन थामा। 1998 में वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तरी गोवा से सांसद बने। इसके बाद वे अक्टूबर 2000 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए, मगर 2002 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में लौट आए। 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को सत्ता में लौटाया और पांच साल तक गृह मंत्री रहे। 2021 में उन्होंने एक बार फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर पोंडा सीट से जीत हासिल की और प्रमोद सावंत मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। रवि नाइक के निधन से गोवा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। वे अपने संतुलित नेतृत्व, संगठनात्मक कौशल और जनसंपर्क की सरलता के लिए जाने जाते थे। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय श्रद्धांजलि देने की घोषणा की है।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की सशर्त दी मंजूरी, अब दिल्ली-एनसीआर की दिवाली होगी पटाखों के संग,

दिवाली पर दो स्लॉट में बेच और फोड़ सकेंगे पटाखे

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को सीमित समय के लिए अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 18 से 21 अक्टूबर तक लोग ग्रीन पटाखे बेच और जला सकेंगे। दिवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को लोग सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 8 से 10 बजे तक, कुल तीन घंटे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अदालत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, लोगों की परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच। सीजेआई गवई ने कहा, हम त्योहारों की खुशी छीनना नहीं चाहते, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता भी नहीं करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी और अवैध बिक्री से अधिक नुकसान होता है। इसलिए ग्रीन पटाखों को सीमित और नियंत्रित दायरे में अनुमति देना व्यावहारिक कदम है। अदालत ने निर्देश दिया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 एनसीआर में आने वाले जिलों में पेट्रोलिंग टीमें नियमित निरीक्षण करें और निर्माताओं को अपने क्यूआर कोड ऑनलाइन अपलोड करने होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। छह साल से जारी ग्रीन पटाखा नीति बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अर्जुन गोपाल केस के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट सामने आया था। पिछले छह वर्षों में इन पटाखों से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) ने इन ग्रीन पटाखों के डिजाइन में अहम भूमिका निभाई थी।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पटाखा निर्माण पर अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेगा ताकि वायु गुणवत्ता पर असर का मूल्यांकन किया जा सके।

भारत को अब एक विश्वस्तरीय रेलवे प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए: वैष्णव

11 सालों में मोदी सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर दिया विशेष ध्यान

नई दिल्ली,(ईएमएस)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में भारतीय रेल ने जबरदस्त प्रगति की है और इसके नतीजे अब साफ नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में 35,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गईं और 46,000 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है और आज उसके शानदार परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 40,000 नए रेल कोच बनाए गए हैं, जो भारत की तकनीकी और निर्माण क्षमता को दर्शाता है।

वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धियां भारतीय रेल के परिवर्तन और एक आधुनिक, टिकाऊ और यात्री-हितैषी परिवहन प्रणाली की दिशा में सरकार की दूरदर्शी सोच को दिखाती हैं।

उन्होंने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेज़ी से काम चल रहा है और अब तक 325 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो गया मैं सूरत और मोरा स्टेशनों पर गया था।

यह 2027 में खुलने वाले पहले हिस्से का हिस्सा होंगे। उन्होंने

कहा कि भारत में अब 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत सेवाएं और 4 नमो भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों में बेहद लोकप्रिय हैं। रेल मंत्री ने सीआईआई को यह आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया और सुझाव दिया कि भारत को अब एक विश्वस्तरीय रेलवे प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए, जो जर्मनी की इननो ट्रेन से भी बड़ी हो।

तमिलनाडु में हिंदी पर बैन की तैयारी- सीएम स्टालिन की भाषाई स्वाभिमान नीति आई फिर चर्चा में

चेन्नइ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित बिल में हिंदी फिल्मों, गानों, विज्ञापन बोर्डों और होर्डिंग्स में हिंदी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रावधान शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने मंगलवार देर रात कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई, जिसमें बिल के मसौदे पर विस्तार से चर्चा हुई। यह बिल 14 से 17 अक्टूबर तक चल रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में लंबे समय से हिंदी भाषा को लेकर विवाद चलता रहा है। डीएमके और अन्य द्रविड़ दल केंद्र की तीन-भाषा नीति का विरोध करते रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कई मौकों पर कहा है कि राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा। मार्च 2025 में पेश किए गए राज्य बजट के दौरान भी स्टालिन सरकार ने एक प्रतीकात्मक भाषाई कदम उठाते हुए बजट दस्तावेजों और सिंबल से रुपए का हिंदी प्रतीक हटाकर तमिल अक्षर का उपयोग किया था, जो रुबाई (रुपया)÷ शब्द का पहला अक्षर है। यह निर्णय उस समय भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था। संभावित प्रभाव और राजनीतिक संदेश प्रस्तावित बिल पारित होने के बाद राज्य में सार्वजनिक स्थलों, विज्ञापनों, सिनेमा हॉलों, रेडियो प्रसारणों और गानों में हिंदी के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है। यदि यह बिल लाकर पारित किया जाता है, तो तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां हिंदी भाषा के सार्वजनिक उपयोग पर औपचारिक प्रतिबंध लागू होगा।

सुकमा में नक्सलियों का बड़ा सरेंडर झटका: 60 में से 27 माओवादी मुख्यधारा में लौटे

सुकमा छत्तीसगढ़ के लाल आतंक को जड़ से मिटाने की दिशा में सुरक्षाबलों की प्रभावी कार्रवाई रंग ला रही है। सोनू दादा समेत कुल 60 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद नक्सली संगठन को एक और भारी झटका लगा है। बुधवार को सुकमा जिले में 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 50 लाख रुपये के इनाम घोषित थे। इनमें दो हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और नियद नेल्ला नार योजना से प्रेरित होकर इन नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पित माओवादियों में एक सीवायसीएम सदस्य, 15 पार्टी सदस्य और 11 अग्र संगठन के सदस्य शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में शामिल हैं: 10 महिलाएं,सबसे बड़े इनामी नक्सली ओयाम लखमू (10 लाख),तीन नक्सली जिन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था,कई अन्य जिन पर 1-3 लाख रुपये तक का इनाम घोषित था इन सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50,000-50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई और शासन की प्रेरक नीतियों के चलते यह सरेंडर नक्सलियों के लिए मुख्यधारा में लौटने का एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। यह घटना छत्तीसगढ़ में नक्सली आंदोलन को गंभीर झटका देने के साथ ही प्रदेश की शांति और विकास की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

विदेश मंत्री मुत्ताकी से मिला भारत में रह रहा अफगान अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधिमंडल

ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और यात्रा नियमों में ढील की मांग की

नई दिल्ली

मातृभूमि छोड़कर भारत में शरण लेने वाले अफगान अल्पसंख्यकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अफगान दूतावास में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात कर अनुरोध किया कि अफगानिस्तान में वर्तमान शासन वहां स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए ठोस कदम उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने अफगान अल्पसंख्यकों के लिए यात्रा नियमों में ढील देने की भी मांग की है, ताकि वे पहले की तरह बिना वीजा के आवेदन किए वहां जा सकें, यदि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तय करती है तो कई लोग व्यापार के लिए वापस जाना चाहेंगे।

उन्होंने मांग की कि अफगानिस्तान सरकार को भारत में अपने मिशन में अफगान अल्पसंख्यकों को नियुक्त करने और उन्हें शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। बैठक के बाद जारी एक बयान के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जैसा कि पिछली सरकार में भी अल्पसंख्यकों को सरकार में प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए, कम से कम दो व्यक्तियों हिंदू और सिख समुदाय से एक-एक शख्स को सरकार में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यकों के संपत्ति अधिकारों और संपदा की बहाली की भी मांग की, जो पिछली सरकार के दौरान छीन ली गई थीं।

भारत में अफगान समुदाय की मदद करने वाले इंडिया वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुत्तकी को अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के इतिहास और उनकी वर्तमान जनसांख्यिकी के बारे में जानकारी दी।

भारतीय विश्व मंच के समन्वय से अफगान अल्पसंख्यक परिषद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में समुदाय के करीब 30 प्रमुख हिंदू-

सिख सदस्य शामिल थे, जो दशकों से भारत में रह रहे थे और उनमें से कई अब भारतीय नागरिकता रखते हैं। बैठक के बाद समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति ने बताया कि विदेश मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि वे हमारे सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। दिल्ली में करीब 5,000 अफगान अल्पसंख्यक रहते हैं। हालांकि ज्यादातर ने भारतीय नागरिकता ले ली है, फिर भी करीब 2000 लोग अफगान नागरिक हैं।

यूएनएचआरसी के 2026-2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया भारत

नई दिल्ली भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 2026-2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह भारत का सातवाँ कार्यकाल होगा, और यह अगले साल पहली जनवरी से शुरू होगा। यूएनएचआरसी के लिए चुने गए 14 सदस्य देश (2026-2028 कार्यकाल) हैं- जिसमें अंगोला, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, भारत, इराक, इटली, मॉरीशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने चुनाव को मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। 47 सदस्यों की मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख निकाय है, जो विश्व में मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण के लिए कार्यरत है। परिषद का गठन महासभा ने 2006 में किया था, जब भारत को पहली बार चुना गया था।

औवेसी ने बिहार चुनाव के लिए आजाद समाज और अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया

पटना बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। तीनों दल मिलकर राज्य की 64 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सीट बंटवारे के तहत एआईएमआईएम 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी। इस गठबंधन को बिहार की राजनीति में नया प्रयोग माना जा रहा है, जो अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की पार्टी ने 2020 में सीमांचल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, और अब वह आजाद समाज पार्टी के दलित आधार और अपनी जनता पार्टी के स्थानीय नेटवर्क के साथ मिलकर प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह गठबंधन पारंपरिक सत्ताधारी दलों की पकड़ को चुनौती देने की कोशिश है। गठबंधन का फोकस सामाजिक समानता, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और जमीनी राजनीति पर होगा। फिलहाल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है, इस लेकर सियासी हलकों में खासा उत्साह है।

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार, कांग्रेस-राजद में 65-55 में फंसा पेंच

कांग्रेस ने 43 सीट पर किए उम्मीदवार चयनित, जल्द हो सकती है नामों की घोषणा

पटना

बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस चुनाव में 65 सीटें चाहती है और राष्ट्रीय जनता दल 55 सीटें देने को तैयार है। इधर पार्टी सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में पहले चरण की जिन सीटों पर सहमति बनी है उनके नाम आज घोषित हो सकते हैं। कांग्रेस ने अब तक कुल 43 सीट पर उम्मीदवार चयनित किए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस 65 सीटों की मांग पर अड़ी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीटों की अदला-बदली को देखते हुए पार्टी 74 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दे रही है। ऐसे कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर दावेदारों से आवेदन मंगाए थे। महागठबंधन समन्वय समिति के समन्वयक तेजस्वी यादव के साथ बातचीत में कोई फार्मूला तय नहीं होने से मंगलवार को दिल्ली में पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पर विचार किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस मंगलवार को भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप नहीं दे सकी है।

दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंगलवार को 18 नामों पर चर्चा हुई। 3 घंटे चली बैठक में इन सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में 40 सीट

की चर्चा हुई। शेष सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए सब कमेटी का गठन किया गया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी मजबूत सीटों पर चर्चा हुई है। अब आगे की तैयारी कर रहे हैं।

कांग्रेस को डर सता रहा है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकट दावेदारों ने जमकर नारेबाजी भी की थी। इस कारण सदाकत आश्रम में हमेशा दिखने वाले नेताजी अब गायब हैं। दरअसल इस बार पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन मंगाए थे। इस कारण दावेदारों की संख्या चार हजार से ज्यादा है। चुनावी साल में संगठन के अभाव में इन दावेदारों के सहारे ही पार्टी ने कार्यक्रमों और अभियान को सफल बनाया। कांग्रेस इन्हें आश्वस्त करती रही कि कार्यक्रमों में मेहनत के अनुसार ही टिकट मिलेगा। नई दिल्ली में दावेदारों ने डेरा जमा लिया है।

नीतीश ने चिराग के कोटे की सीटों पर उतार दिए प्रत्याशी.....अब एनडीए में आएगा भूचाल

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट बंटवारे बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो चुका है। जेडीयू, बीजेपी के बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे है, लेकिन अपनी मजबूत सीटें किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर एनडीए के सीट शेयरिंग के समझौते का फॉर्मूला बिगाड़ दिया है। एनडीए के सीट शेयरिंग के बाद से उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी नाराज हैं और अब नीतीश कुमार ने जिस तरह चिराग पासवान को मिली पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे लग रहा हैं कि एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा?

जेडीयू ने बुधवार को जिन 57 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उसमें पांच सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कि ये चिराग के कोटे में रहेंगी। सीट बंटवारे में एलजेपी को कुल 29 सीटें मिली हैं। इसमें मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा भी थी, जिस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजगीर सीट पर मौजूदा विधायक कौशल किशोर और सोनबरसा के विधायक व मंत्री रत्नेश सदा को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेडीयू ने एकमा सीट पर पूर्व विधायक धूमल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मोरवा सीट पर विद्यासागर निषाद और गायघाट सीट से कोमल सिंह को मैदान में उतारा है। सीट बंटवारे में ये पांचों सीटें चिराग के खाते में गई थीं, जिस पर नीतीश ने अपने प्रत्याशी उतारकर साफ संदेश दिया हैं कि वे किसी भी सूरत में अपनी मजबूत सीटें नहीं छोड़ने वाले है।

वहीं मांझी ने भी ऐलान किया है कि वे चिराग को मिली मखदुमपुर सीट पर अपना प्रत्याशी उतरने वाले है। इस तरह से एनडीए में अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो गई है। चिराग ने जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, उसमें से कई सीटें ऐसी हैं, जिन पर जेडीयू और बीजेपी का कब्ज़ा है। बीजेपी भले ही अपनी जीती सीटें छोड़ रही हो, लेकिन जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है।। चिराग की दावे वाली चार सीटों पर बीजेपी का कब्ज़ा है,तब तीन सीटों पर जेडीयू के विधायक हैं। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पिछले एक साल से पार्टी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह सीट शेयरिंग का ऐलान होते ही मांझी से लेकर कुशवाहा और नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए, उससे सब बेकार हो गया। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी के लिए सियासी संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशक: सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)